UPHIN/25/A4962

फरवरी–2026

मूल्य ₹ 30/–

न्यूज ड्रिफ्ट

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

उत्तर प्रदेश दिवस 2026

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

खुशहाल किसान
उत्तर प्रदेश की पहचान

गेहूं खरीद वर्ष 2026-27 हेतु
पंजीकरण/अपडेशन प्रारम्भ

गेहूं विक्रय हेतु कृषक बन्धु पंजीकरण कराएं तथा गत वर्ष बिक्री कर चुके कृषक बन्धु पूर्व पंजीकरण को अपडेट कराकर समर्थन मूल्य का लाभ उठाएं

गेहूं खरीद में पिछले वर्ष के समर्थन मूल्य के सापेक्ष ₹160/- की भारी वृद्धि करते हुए

गेहूं का समर्थन मूल्य
₹2,585/- प्रति कुंतल

निर्धारित किया गया है

क्रय की अवधि

17 मार्च से 15 जून, 2026 तक

क्रय केन्द्र प्रात: 9:00 से सायं 6:00 बजे तक संचालित रहेंगे

किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जायेगा।

कृषक बन्धु अपने जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, उस बैंक खाते को आधार सीडेड एवं बैंक शाखा द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप करा लें।

बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है कि उसमें पिछले तीन महीने में धनराशि का लेन-देन किया गया हो।

कृषक भाइयों से अपील

- गेहूं विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, मोबाइल फोन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण आवश्यक।
- रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं विक्रय करने वाले कृषकों को गेहूं विक्रय हेतु पुन: पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, परन्तु पंजीकरण को अपडेट कराना होगा।
- गेहूं बिक्री हेतु OTP आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक भाई पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित करायें एवं SMS द्वारा प्रेषित OTP भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें।
- बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य।

किसान पंजीकरण/अपडेशन, भूमि के रकबे का सत्यापन, खरीद व MSP पेमेंट की अद्यतन स्थिति जानने हेतु गूगल प्ले स्टोर/QR कोड के माध्यम से UP Kisan Mitra मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

वर्तमान में संचालित धान क्रय केन्द्रों पर भी पंजीकरण/अपडेशन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

कृषक किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या संबंधित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश

न्यूज ड्रिफ्ट

वर्ष–1 अंक–02फरवरी–2026

संरक्षक
पं० आदित्य द्विवदी

संपादक
रवि कान्त

सह संपादक
श्वेता शुक्ला

ब्यूरो चीफ लखनऊ
पंकज द्विवेदी

ग्राफिक्स डिजाइनर
अरूण मिश्र

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक

''यह मासिक पत्रिका रवि कान्त द्वारा 537भ /236 भरत नगर, मोहिबुल्लापुर लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226021 से रवि कान्त के स्वामित्व में प्रकाशित की जाती है, जिसके संपादक रवि कान्त हैं और यह नीलम प्रिंटिंग प्रेस, 41/381, नरही लखनऊ उत्तर प्रदेश–226001 पर नीलम श्रीवास्तव द्वारा मुद्रित की जाती है।''

Mob. 9451760655
Email :-
newsdrift19@gmail.com
Website :-
WWW.NEWSDRIFT.IN
RNI-UPHIN/25/A4962

पत्रिका में प्रकाशित लेख व समाचारों में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। उसका लेखक ही उत्तरदायी होगा।

समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र माननीय न्यायालय लखनऊ होगा।

यूजीसी के नए नियमः सामाजिक न्याय का सशक्तिकरण या सवर्ण–दलित टकराव– 05

कर्तव्य पथ पर 77वां गणतंत्रः 2026 की परेड में दिखी 'विकसित भारत' की झलक–15

आईसीसी का वेन्यू बदलने से इनकारः बांग्लादेश टी 20 विश्व कप से बाहर –21

लोकतंत्र का मुखौटा और विस्तारवाद का चेहरा– 26

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 – 29

शंकराचार्य बनाम यूपी सरकार मामले की जमीनी हकीकत – 32

सम्पादक की कलम से ....

न्यूज ड्रिफ्ट: शोर से अलग एक शुरुआत

आज का समय सूचनाओं की बाढ़ का है। हर पल, हर स्क्रीन पर खबरें हैं-तेज, चटख और अक्सर अधूरी। इस शोर में सच कई बार दब जाता है, संदर्भ खो जाता है और समझ पीछे छूट जाती है। ऐसे दौर में न्यूज ड्रिफ्ट की यह शुरुआत उसी खामोशी से जन्म लेती है, जो शोर से अलग होकर सोचने का अवसर देती है।

न्यूज ड्रिफ्ट का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि खबर के अर्थ को सामने रखना है। हम मानते हैं कि पत्रकारिता का काम सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि समय रहते चेतावनी देना, सवाल उठाना और नागरिकों को समझ से लैस करना है।

यह पत्रिका राजनीति, समाज, पर्यावरण और नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दों को तथ्यों, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करने का संकल्प लेती है। हम पक्षधरता से अधिक पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं; शोर से अधिक संदर्भ में; और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से अधिक दीर्घकालिक सोच में। न्यूज ड्रिफ्ट उस पत्रकारिता का पक्षधर है, जो डर नहीं फैलाती-समझ पैदा करती है।

पत्रिका के रूप में यह शुरुआत हमारे लिए एक वादा है- पाठकों से भी और स्वयं से भी। यह वादा कि हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, जटिल सवालों से नहीं बचेंगे और जनहित को प्राथमिकता देंगे। हमें भरोसा है कि पाठक भी ऐसी पत्रकारिता के सहभागी बनेंगे, जो खबर को उपभोग नहीं, संवाद बनाती है।

यह पहला कदम है। आगे की राह लंबी है और चुनौतियाँ भी होंगी। लेकिन यदि पत्रकारिता को फिर से भरोसे, विवेक और संवेदना से जोड़ना है, तो शुरुआत शोर से अलग होकर ही करनी होगी। न्यूज ड्रिफ्ट उसी अलग शुरुआत का नाम है, जहाँ खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं जातीं, समझी जाती हैं।

संपादक

रवि कान्त

यूजीसी के नए नियम: सामाजिक न्याय का सशक्तिकरण या सवर्ण-दलित टकराव की नई जमीन

भारतीय उच्च शिक्षा का परिदृश्य इस समय एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा पेश किए गए 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' ने देश के शैक्षणिक गलियारों में एक ऐसी बहस छेड़ दी है, जो केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि 'अधिकार और असुरक्षा' के नए सामाजिक संघर्ष की ओर इशारा कर रही है। एक तरफ सामाजिक न्याय की पक्षधर शक्तियां इसे 'ऐतिहासिक' मान रही हैं, तो दूसरी तरफ सवर्ण संगठनों ने इसे 'प्रतिशोध का हथियार' करार दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का परिचय

- **परिचय:** यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- **स्थापना:** 1956 में संसद के अधि नियम द्वारा।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली (6 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ)।
- **मुख्य कार्य:**
- **मानक तय करना:** विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, परीक्षा और रिसर्च के स्तर को निर्धारित करना।
- **अनुदान (Funding):** कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सरकारी फंड बाँटना।
- **मान्यता:** संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा देना और डिग्रियाँ प्रदान करने की अनुमति देना।
- **निगरानी:** शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना और 'फर्जी विश्वविद्यालयों' को चिह्नित करना।

क्या है यूजीसी एक्ट 2026:

UGC ने भारतीय विश्वविद्यालयों में निष्पक्षता और भेदभाव-मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से UGC (प्रमोशन ऑफ इक्विटी) रेगुलेशन 2026 लागू करने का निर्णय लिया। इसका मुख्य

लक्ष्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और दिव्यांगजनों के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को जड़ से मिटाना है।

अधिनियम के प्रमुख स्तंभः

- **Equal Opportunity Centre (EOC):** हर संस्थान को अनिवार्य रूप से इस केंद्र की स्थापना करनी होगी, जो शिकायतों का निपटारा करेगा।
- **24×7 हेल्पडेस्कः** छात्रों और कर्मचारियों के लिए हर समय उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल।
- **इक्विटी एंबेसडरः** संस्थानों में छात्र समूहों के बीच से 'एंबेसडर' नियुक्त किए जाएंगे, जो भेदभाव पर निगरानी रखेंगे।
- **दंडात्मक प्रावधानः** यदि कोई विश्वविद्यालय नियमों का पालन नहीं करता, तो UGC उसका अनुदान (Grant) रोक सकता है या उसकी मान्यता रद्द कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोकः

जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर 19 मार्च 2026 तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को न्यायसंगत होना चाहिए, लेकिन नियमों की भाषा ऐसी न हो जो समाज को और अधिक विभाजित कर दे।

अदालत ने विशेष रूप से 'जाति-आधारित छात्रावासों' के विचार और 'भेदभाव' की अत्यधिक व्यापक परिभाषा पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट का मानना है कि इससे परिसरों में सौहार्द बिगड़ सकता है। अब पूरी नजर 19 मार्च की सुनवाई पर है, तब तक 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।

	UGC Rule 2012	UGC Rule 2026
उद्देश्य:	उच्च शिक्षा में भेदभाव को रोकना	समानता, गरिमा, सुरक्षा और समावेश को बढ़ावा
मुख्य फोकस:	ST-SC के छात्रों पर केंद्रित	ST, SC, OBC, लैंगिक, अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्ति
कौन-कौन सम्मिलित :	मुख्य रूप से छात्र	छात्र, शिक्षण संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारी
शिकायत प्राधिकरण:	भेदभाव-विरोधी अधिकारी	बहुसदस्यीय समता समिति
शिकायत दर्ज करने का तरीका:	लिखित और ऑफलाइन	ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन माध्यम
कार्यवाही के लिए समय सीमा:	60 दिन तक	24 घंटे के भीतर समिति की बैठक और 7 दिनों के भीतर कार्यवाही

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को न्यायसंगत होना चाहिए, लेकिन नियमों की भाषा ऐसी न हो जो समाज को और अधिक विभाजित कर दे

सवर्ण समाज का विरोध और 'S-4' का उदय

नियमों के अधिसूचित होते ही देश के कई हिस्सों में, विशेषकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सवर्ण संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर 'सवर्ण समाज समन्वय समिति (S-4)' का गठन किया है।

विरोधियों के तर्कः

- **झूठे मामलों का डरः** प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियमों में 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन' (उल्टा भेदभाव) की संभावना है, जहाँ अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को बिना पुख्ता सबूतों के निशाना बनाया जा सकता है।
- **प्रशासनिक असंतुलनः** आलोचकों का तर्क है कि 'इक्विटी स्क्वाड' जैसे प्रावधान संस्थानों के शैक्षणिक माहौल को राजनीतिक अखाड़े में तब्दील कर देंगे।
- **सबूत का भारः** यूजीसी के प्रस्तावित नियमों में कुछ धाराओं में संकेत

था कि शिकायत होने पर आरोपी (प्रोफेसर या संस्थान) को ही साबित करना होगा कि उसने भेदभाव नहीं किया है।

आंकड़ों का आईना:

विरोध के बीच यूजीसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े बताते हैं कि संस्थानों में स्थिति चिंताजनक है। पिछले पांच वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

शैक्षणिक वर्ष	प्राप्त शिकायतें (UGC डेटा)
2019–20	173
2020–21	182
2021–22	186
2022–23	241
2023–24	378
कुल (5 वर्ष)	1,160 शिकायतें

विशेषज्ञों का कहना है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के दशकों बाद भी उच्च पदों पर वंचित वर्गों की भागीदारी 15% से अधिक नहीं हो पाई है, जो इस नए और कड़े कानून की आवश्यकता को बल देता है।

पुराने और नए नियमों के बीच मुख्य अंतर:

यूजीसी के 2012 और 2026 के नियमों के बीच सबसे बड़ा अंतर दायरे और संरचना को लेकर है। एक तरफ 2012 के नियम थे जो व्यवहार आधारित और छात्र-केंद्रित थे, वहीं 2026 के नए नियम संस्थागत ढांचे और निगरानी तंत्र पर ज्यादा निर्भर हैं। दोनों नियमों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित थे:-

UGC ने 13 जनवरी, 2026 को नए नियम अधिसूचित किए, जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए इक्विटी कमेटी का गठन अनिवार्य होगा। हम UGC के बारे में बता रहे हैं।

- UGC (University Grants Commission) भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है।
- इसकी स्थापना 1956 में संसद के अधिनियम के जरिए की गई थी। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- देश के विश्वविद्यालयों को मान्यता देना UGC की प्रमुख जिम्मेदारी है।
- केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों को फंड और ग्रांट भी UGC के जरिए मिलती है।
- UGC यह तय करता है कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट किस मानक पर दिए जाएंगे।
- NET और JRF जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के नियम UGC बनाता है।
- सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी UGC के दायरे में आती हैं।
- नई शिक्षा नीति (NEP) के बाद UGC ने क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट जैसे नए नियम लागू किए हैं।
- हाल के वर्षों में UGC के कुछ नियमों को लेकर छात्र संगठनों और शिक्षाविदों ने विरोध भी जताया है।

- **दायरा और पहुँच**
  - » 2012 विनियम मुख्य रूप से छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव पर केंद्रित थे।
  - » 2026 विनियम छात्रों के साथ-साथ शिक्षक, कर्मचारी और प्रबंधन को भी दायरे में लाते हैं।
- **समानता की परिभाषा**
  - » 2012 में समानता को छात्र-व्यवहार और सुविधाओं से जोड़कर देखा गया।
  - » 2026 में समानता को संस्थान की नीतियों, प्रक्रियाओं और ढांचे से जोड़कर परिभाषित किया गया।
- **भेदभाव की प्रकृति**
  - » 2012 में भेदभाव को ज़्यादातर प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाले व्यवहार के रूप में देखा गया।
  - » 2026 में भेदभाव को प्रत्यक्ष (Explicit) और अप्रत्यक्ष/अंतर्निहित (Implicit)—दोनों रूपों में माना गया।

- **संरक्षित वर्गों का दायरा**
  - » 2012 में मुख्य जोर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों पर था।
  - » 2026 में एससी/एसटी के साथ-साथ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया।
- **संस्थागत ढांचा**
  - » 2012 में हर संस्थान में केवल Equal Opportunity Cell और Anti-Discrimination Officer का प्रावधान था।
  - » 2026 में समान अवसर केंद्र, समता समिति, समता दल और समता दूत जैसी नई संरचनाएं जोड़ी गई।
- **निगरानी और रिपोर्टिंग**
  - » 2012 में निगरानी मुख्य रूप से आंतरिक और सीमित थी।
  - » 2026 में नियमित निगरानी, सार्वजनिक रिपोर्ट और कैंपस-स्तरीय मॉनिटरिंग का प्रावधान किया गया।
- **शिकायत कौन कर सकता है**
  - » 2012 में शिकायत करने का अधिकार छात्र या उनके अभिभावकों तक सीमित था।
  - » 2026 में कोई भी हितधारक शिकायत दर्ज कर सकता है।
- **शिकायत प्रक्रिया**
  - » 2012 में शिकायत प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और संस्थान -केंद्रित थी।
  - » 2026 में ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन व समयबद्ध प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया।
- **अपील का अधिकार**
  - » 2012 में अपील संस्थान प्रमुख के पास की जाती थी।
  - » 2026 में अपील के लिए लोकपाल की व्यवस्था की गई।
- **नियमों की प्रकृति**
  - » 2012 के विनियम व्यवहार-आधारित व अपेक्षाकृत संक्षिप्त थे।
  - » 2026 के विनियम संरचनात्मक, विस्तृत और बहु-स्तरीय हैं।

विश्लेषणः टकराव की नई

विवाद का आधार

- इस पूरे विवाद के पीछे केवल नियम नहीं, बल्कि सामाजिक 'वर्चस्व' की जंग है। जहाँ एक ओर दलित और पिछड़ा वर्ग इसे कैंपस में अपनी 'जान और सम्मान' की सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं, वहीं सवर्ण वर्ग इसे अपनी 'मेरिट और स्वायत्तता' पर हमला मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्वामी आनंद स्वरूप जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के बयानों ने इस आग में घी डालने का काम किया है।
- यूजीसी रेगुलेशन 2026 एक दोधारी तलवार है। यदि यह सही ढंग से लागू हुआ, तो यह भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों के अनुरूप 'समावेशी' बनाएगा। लेकिन यदि इसके प्रावधानों में अस्पष्टता रही, तो यह संस्थानों को केवल अदालती मुकदमों का अड्डा बना देगा। अगली सुनवाई (19 मार्च) यह तय करेगी कि भारत के शैक्षणिक संस्थान 'समरसता के केंद्र' बनेंगे या 'वैचारिक संघर्ष' के।

उत्तर प्रदेश दिवस 2026: ‘उत्तम प्रदेश’ से ‘उद्यम प्रदेश’ बनने की गौरवगाथा

24 जनवरी का दिन उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता और सामर्थ्य को पहचानने का पर्व है। 2026 का ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ खास है, क्योंकि आज राज्य ने अपनी पहचान एक ‘बीमारू प्रदेश’ से बदलकर देश के ‘ग्रोथ इंजन’ के रूप में स्थापित कर ली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सांस्कृतिक विरासत से लेकर जेवर के आधुनिक रनवे तक, यूपी की यह यात्राा ‘उत्तम से उद्यम’ की ओर बढ़ते कदम की महागाथा है

आर्थिक परिदृश्य: $1 ट्रिलियन का रोडमैप:

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026 तक अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा था, उसके क्रियान्वयन में 'ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी' (GBC) मील का पत्थर साबित हुई हैं।

- **जीएसडीपी और प्रतिव्यक्ति आय में छलांग:** वर्ष 2024-2025 में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आकलित हुई है, जो गाठ वर्ष की तुलना में 13 .4 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित करती है। वही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आकलित हुई है जो वर्ष 2016-2017 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपये के दो गुने से अधिक है।
- राज्य का कर राजस्व 0.86 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि सार्वजनिक ऋण - से - जीएसडीपी अनुपात 2016-17 में 29.3% के उच्च स्तर से घटकर 2024-25 में 28 प्रतिशत हो गया है, जिससे यह एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) सीमाओं के भीतर बना हुआ है।
- **ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 4.0:** राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया। जनवरी 2026 के अंत तक राज्य में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एम ओ यू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनमे से लगभग 15 लाख करोड़ रु. से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।
- **औद्योगिक गलियारे:** एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे 'इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स' ने लॉजिस्टिक्स लागत को घटाया है।
- **ODOP (एक जनपद एक उत्पाद):** इस योजना ने यूपी के एमएसएमई (MSME) निर्यात को 2 लाख करोड़ के पार पहुँचाने में मदद की है।
- **डिफेंस कॉरिडोर:** स्वदेशी रक्षा विनिर्माण ने बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दिया है।

सुशासन और सुगमता: निवेश का नया स्वर्ग

- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** 'निवेश मित्र' और 'निवेश सारथी' जैसे पोर्टल्स के माध्यम से यूपी अब व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में देश के अग्रणी राज्यों में स्थिर है।
- **राजस्व आधिक्य:** बेहतर कर संग्रह और GST सुधारों के कारण यूपी का राजकोषीय प्रबंधन अब एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
- **सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्र:** औद्योगिक क्लस्टर्स में विशेष पुलिस बल और UP-112 की सक्रियता ने सुरक्षा का वह माहौल बनाया है जिसकी कमी 2017 से पहले खलती थी।

अपराध पर 'जीरो टॉलरेंस' और सुरक्षा का भरोसा

निवेश के लिए सबसे पहली शर्त 'सुरक्षा' होती है। यूपी ने इस मोर्चे पर कड़े सुधार किए हैं:

- **सुरक्षा और कानून व्यवस्था:** पिछले 9 वर्षों में संगठित अपराध पर अंकुश और दंगों की अनुपस्थिति ने वैश्विक निवेशकों (जैसे सैमसंग, पेप्सिको और टाटा) का भरोसा जीता है।
- **सेफ सिटी प्रोजेक्ट:** 17 नगर निगमों को 'सेफ सिटी' के रूप में विकसित करना व UP-112 की त्वरित रिस्पांस प्रणाली ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा का माहौल बनाया है।
- **मिशन शक्ति:** इसके अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामजिक सहभागिता को नयी गति मिलती है।
- **अपराध में कमी:** वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मानलों में क्रमश 89 प्रतिशत, 85 प्रतिशत , 47 प्रतिशत , 70 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की कमी हुई है।
- **महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी:** वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु , बलात्कार और शीलभंग के मामलों में क्रमशः 48 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की कमी आयी।
- **अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न में कमी:** इनके खिलाफ अपराधों में 2016 के मुकाबले हत्या, आगजनी, बलात्कार, गंभीर चोट के

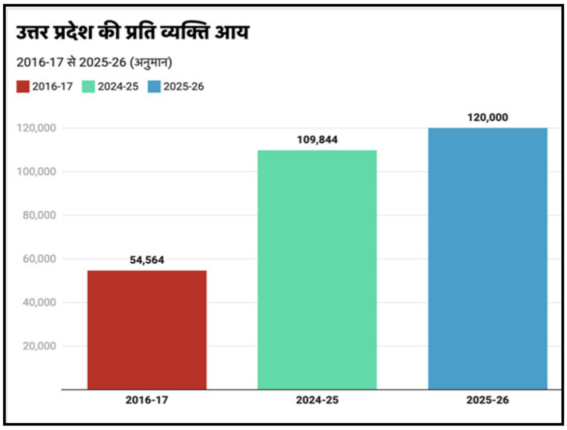

मामलों में क्रमशः 43 प्रतिशत, 94 प्रतिशत और 32 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी आयी।

इन्फ्रास्ट्रक्चरः उड़ान भरता नया उत्तर प्रदेश

- उत्तर प्रदेश अब 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में जाना जाता है।
- उत्तर प्रदेश खुद को देश के एक्सप्रेसवे हब के रूप में स्थापित कर रहा है, जहां सात एक्सप्रेसवे चालू हैं, तीन निर्माणाधीन हैं और 12 प्रस्तावित हैं, जिससे राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल संख्या 22 हो गई है।
- जिसने से महत्वपूर्णः-
  - **गंगा एक्सप्रेसवेः** गंगा एक्सप्रेसवे (मेरठ से प्रयागराज) जो पश्चिमी यूपी के औद्योगिक हब को पूर्वी यूपी के आध्यात्मिक केंद्रों से मात्र 6-7 घंटों में जोड़ता है।
  - **पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेः** इन एक्सप्रेसवे ने पिछड़े माने जाने वाले क्षेत्रों को सीधे दिल्ली और लखनऊ के बाजारों से जोड़ दिया है, जिससे यहाँ 'इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स' का विकास तेज हुआ है।
- राज्य की अंतर्देशीय जलमार्गों में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है, क्योंकि इससे होकर 11 राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरते हैं, और वाराणसी मल्टी-मोडल टर्मिनल पहले से ही चालू है।

एविएशन हबः 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य

उत्तर प्रदेश ने हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 'क्वांटम जंप' ली है।

- **जेवर (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट):** जनवरी 2026 के अंत तक जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होना उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। यह एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है, जो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के भार को साझा कर रहा है।
- **अयोध्या (महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट):** राम मंदिर के बाद इस एयरपोर्ट ने वैश्विक पर्यटकों के लिए 'गेटवे' का काम किया है।
- **वर्तमान स्थितिः** यूपी में अब 21 एयरपोर्ट (इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिलाकर) क्रियाशील हैं, जो 2017 से पहले मात्र 4 थे।

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्सः उत्तर प्रदेश बना भारत का नया 'सिलिकॉन वैली'

- उत्तर प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जो छलांग लगाई है, उसने दक्षिण भारत के राज्यों के एकाधिकार को चुनौती दी है। 2026 तक की स्थिति के अनुसार, यूपी अब केवल 'बैक ऑफिस' नहीं, बल्कि 'इनोवेशन हब' बन चुका है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडाः वैश्विक आईटी पावरहाउस

- नोएडा और ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र अब वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनियों की पहली पसंद है।
- **दिग्गज कंपनियों का आगमनः** माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft), गूगल (Google) और टीसीएस (TCS) जैसी कंपनियों ने यहाँ अपने सबसे बड़े परिसरों (Campuses) का विस्तार किया है।
- **डाटा सेंटर हबः** उत्तर प्रदेश की 'डाटा सेंटर नीति' के कारण ग्रेटर नोएडा एशिया के सबसे बड़े डाटा

सेंटर हब के रूप में उभरा है। 'योटा डी-1' जैसे केंद्रों ने यूपी को डिजिटल संप्रभुता और स्टोरेज के मामले में देश में शीर्ष पर ला खड़ा किया है।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग

- **मोबाइल उत्पादन:** भारत में बनने वाले हर 10 में से लगभग 6 मोबाइल फोन अब उत्तर प्रदेश में असेंबल या निर्मित हो रहे हैं। सैमसंग का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना इसका केंद्र है।
- **सेमीकंडक्टर नीति:** यूपी सरकार की नई सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन नीति के तहत जेवर एयरपोर्ट के पास 'सेमीकंडक्टर पार्क' विकसित किया जा रहा है, जिसने वैश्विक चिप निर्माताओं को आकर्षित किया है।

लखनऊ और टियर-2 शहरों का उदय:

आईटी सेक्टर अब केवल नोएडा तक सीमित नहीं है:

- **लखनऊ आईटी सिटी:** सुल्तानपुर रोड पर स्थित आईटी सिटी अब पूरी तरह क्रियाशील है, जहाँ सॉफ्टवेयर विकास और बीपीओ (BPO) सेक्टर में हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
- **टियर-2 क्रांति:** गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया' (STPI) के माध्यम से आईटी इकोसिस्टम का विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य 'रिवर्स माइग्रेशन' (प्रतिभाओं की घर वापसी) को बढ़ावा देना है।

स्टार्टअप और एआई रिवोल्यूशन

- **एआई सिटी (लखनऊ):** उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत की पहली 'एआई सिटी' (AI City) विकसित कर रही है। यह परियोजना जनवरी 2026 तक अपने उन्नत चरण में है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है।
- **स्टार्टअप रैंकिंग:** 'यूपी स्टार्टअप नीति' के कारण राज्य अब स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 'एस्पायरिंग लीडर्स' से बढ़कर 'टॉप परफॉर्मर्स' की श्रेणी में आ गया है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण: विरासत का गौरव

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर्यटन तेजी से बढ़ा है। पर्यटन नीति-2022, महाकुंभ-2025 और निवेश योजनाओं से 156.18 करोड़ पर्यटक पहुंचे।
- धार्मिक, सांस्कृतिक और ईको टूरिज्म के विकास से यूपी देश का प्रमुख पर्यटन हब बन रहा है।

धार्मिक पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था:

- उत्तर प्रदेश 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्यटन आधारित विकास रणनीति को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में मजबूत कर रहा है।हाल ही में पर्यटन विभाग, राज्य के सकल मूल्य वर्धित में पर्यटन के योगदान को 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने और भारत के पर्यटन सकल मूल्य वर्धित में यूपी की हिस्सेदारी को 16 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा।

मानक	2017 से पहले की स्थिति	वर्त्तमान स्थिति
पर्यटक संख्या	सालाना लगभग 20-22 करोड़।	156.18 करोड़ (वर्ष 2025 का रिकॉर्ड)।
अयोध्या की छवि	टेंट में रामलला, बुनियादी सुविधाओं का अभाव।	भव्य राम मंदिर, 50 करोड़+ श्रद्धालु (2 वर्ष में)।
काशी का स्वरूप	संकरी और गंदगी भरी गलियां।	भव्य 'काशी विश्वनाथ धाम' और गंगा क्रूज पर्यटन।
वैश्विक पहचान	अपराध और अराजकता के लिए चर्चित।	'महाकुंभ' और 'दीपोत्सव' का वैश्विक ब्रांड।

- **महाकुंभ 2025:** प्रयागराज में आयोजित 'महाकुंभ 2025' उत्तर प्रदेश की नई पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण बना। इस आयोजन में रिकॉर्ड 66.30 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा है। AI-आधारित भीड़ प्रबंधन और 'लॉस्ट एंड फाउंड' सेंटर ने वैश्विक स्तर पर सुशासन का लोहा मनवाया।

उपेक्षित धरोहरों का उदय:

सांस्कृतिक पुनर्जागरण अब केवल बड़े केंद्रों तक सीमित नहीं है:

- **नेमिशारण्य (सीतापुर):** 'श्रीनैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद' के माध्यम से 88,000 ऋषियों की इस भूमि का कायाकल्प पहले चरण में पूर्ण हो चुका है।

- **विन्ध्य कॉरिडोर:** मिर्जापुर स्थित माँ विन्ध्यवासिनी धाम अब त्रिकोण परिक्रमा के लिए पूरी तरह तैयार और भव्य है।
- **बुद्ध सर्किट:** कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती को जोड़ने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं ने विदेशी पर्यटकों (खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया) को आकर्षित किया है।
- **पर्यटन में प्रथम:** यूपी अब घरेलू पर्यटकों के आगमन में देश में प्रथम स्थान पर है।
- **रोजगार सृजन:** सांस्कृतिक पर्यटन ने पिछले 9 वर्षों में सेवा क्षेत्र (होटल, गाइड, परिवहन) में 1.5 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।

बेड एंड ब्रेकफास्ट (होमस्टे) नीति-2025 के तहत, पर्यटन स्थलों के आसपास रहने वाले लोग अपने एक से छह कमरों वाले आवास को होमस्टे के रूप में पंजीकृत कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

- **हस्तशिल्प का मेल:** ODOP (एक जनपद एक उत्पाद) को सांस्कृतिक मेलों और दीपोत्सव जैसे आयोजनों से जोड़ने से स्थानीय शिल्पियों की आय में 30-40% की वृद्धि हुई है।

सामाजिक क्षेत्र:

- सर्वेक्षण में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 5.46 करोड़ लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत कवरेज और लगभग सार्वभौमिक बाल टीकाकरण शामिल है।
- कन्या सुमंगला योजना से 26.81 लाख से अधिक लड़कियों को लाभ मिला है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में भारी वृद्धि देखी गई है।
- राज्य ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें 10.22 करोड़ से अधिक जन धन खाते हैं और ऋण-जमा अनुपात बढ़कर 60.39 हो गया है।

हरित ऊर्जा क्रांति:

उत्तर प्रदेश अब केवल श्कोयलेश पर निर्भर नहीं है, बल्कि सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा का केंद्र बन रहा है।

- **बुंदेलखंड सौर ऊर्जा:** जालौन और झांसी में स्थापित विशाल सौर पार्कों के साथ बुंदेलखंड अब राज्य का श्पावर बैंकश है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन नीति:** 2026 तक राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित किया है, जो शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ता कदम है।
- **अयोध्या:** देश की पहली मॉडल सोलर सिटी- यहाँ की गलियों से लेकर सरयू में चलने वाली नौकाओं तक, सब कुछ अब सौर ऊर्जा से संचालित है।

लॉजिस्टिक्स और 'लैंड–लॉक' होने का अंत

यूपी एक भू-आबद्ध राज्य था, लेकिन अब यह समुद्र से 'डिजिटली और फिजिकली' जुड़ गया है।

- **मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स:** दादरी और बोराकी में बन रहे विशाल हब यूपी के माल को सीधे वैश्विक बंदरगाहों तक पहुँचा रहे हैं।
- **फ्रेट कॉरिडोर:** समर्पित माल ढुलाई गलियारों ने लॉजिस्टिक्स समय को 50% तक कम कर दिया है, जिससे निर्यातकों के लिए यूपी पहली पसंद बना है।

'अन्नदाता से एग्रो–उद्यमी' राज्य

कृषि निर्यात और मूल्य संवर्धन:

यूपी अब कच्चे माल के बजाय 'वैल्यू एडेड' उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है:

- **जेवर एग्रो-एक्सपोर्ट हब:** नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित विशेष प्रसंस्करण जोन ने यूपी के किसानों को सीधे लंदन और दुबई के बाजारों से जोड़ दिया है।
- **जीआई टैग की ताकत:** जनवरी 2026 तक यूपी के 70 से अधिक कृषि उत्पादों के जीआई टैग (GI Tag) हैं (जैसे काला नमक चावल, महोबा का पान, बनारसी लंगड़ा आम)। इनके निर्यात में पिछले 2 वर्षों में 120% की वृद्धि दर्ज की गई है।

डिजिटल और स्मार्ट फार्मिंग:

तकनीक ने खेती की लागत कम और मुनाफा अधिक किया है:

- **डिजिटल क्रॉप सर्वे:** यूपी देश का पहला राज्य बना है जिसने अपने सभी 75 जिलों में 'डिजिटल फसल सर्वेक्षण' पूरा किया है। इससे किसानों को बीमा दावों और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मिल रहा है।
- **ड्रोन क्रांति:** 'नमो ड्रोन दीदी' और 'एग्री-ड्रोन' के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव अब मिनटों में हो रहा है। जनवरी 2026 तक राज्य के 10,000 से अधिक गाँवों में ड्रोन तकनीक का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो चुका है।

प्राकृतिक खेती और जैविक

गलियारा:

- **गंगा और बुंदेलखंड का नया मॉडल:** गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5 किमी के दायरे में और पूरे बुंदेलखंड को 'प्राकृतिक खेती' के हब के रूप में विकसित किया गया है।
- **सिक्किम की तर्ज पर विकास:** सरकार के प्रयासों द्वारा बुंदेलखंड अब भारत का अगला 'ऑर्गेनिक हब' बनने की दिशा में है।

चीनी और इथेनॉल: 'अन्नदाता' अब 'ऊर्जादाता'

- **इथेनॉल हब:** उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक है। प्रदेश के भीतर 105.25 करोड़ लीटर की खपत और अन्य राज्यों को 40.96 करोड़ लीटर की सप्लाई ने यूपी को एथेनॉल का नेशनल हब बना दिया है।
- **गन्ना भुगतान:** पिछले 9 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कर सरकार ने किसानों की आर्थिक रीढ़ मजबूत की है।

उत्तर प्रदेश आज सांख्यिकी और अस्मिता दोनों ही मोर्चों पर विजेता बनकर उभरा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों वाली 'सांस्कृतिक विरासत' और जेवर के आधुनिक रनवे वाली 'उद्यम दृष्टि' का यह अनूठा संगम ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है।

$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का रोडमैप अब केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि 25 करोड़ जनता का साझा संकल्प बन चुका है। बीमारू प्रदेश की बेड़ियाँ तोड़कर, अपराध पर प्रहार कर और सुशासन को धरातल पर उतारकर उत्तर प्रदेश ने सिद्ध कर दिया है कि यदि नेतृत्व में इच्छाशक्ति हो, तो भूगोल और भाग्य दोनों बदले जा सकते हैं।

आज का उत्तर प्रदेश 'समस्या' नहीं, बल्कि भारत की हर समस्या का 'समाधान' है। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस बात का साक्षी है कि 'उत्तम प्रदेश' ने 'उद्यम प्रदेश' की राह पकड़ ली है, और यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। यह नए भारत का वह नया उत्तर प्रदेश है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है और जिसकी आँखें भविष्य के आसमान पर टिकी हैं।

कर्तव्य पथ पर 77वां गणतंत्रः 2026 की परेड में दिखी 'विकसित भारत' की झलक

26 जनवरी 2026 की सुबह जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कुहासा छंटा, तो भारत के इतिहास का एक नया अध्याय सामने था। देश अपने 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा था, लेकिन इस बार का उत्सव साधारण नहीं था। यह उस भारत की तस्वीर थी जो अपनी आजादी के 'अमृत काल' से निकलकर 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य की ओर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। इस साल की परेड में न केवल हमारी सैन्य शक्ति का लोहा माना गया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और तकनीक के क्षेत्र में हमारी छलांग ने दुनिया को चकित कर दिया।

क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस?

गणतंत्र दिवस भारत की राष्ट्रीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी दिन 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही देश की 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में औपचारिक तौर पर स्थापना हुई। बेशक, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया था। लेकिन कानून, संस्थागत जवाबदेही और नागरिकों की इच्छा पर आधारित स्वशासन के रूप में भारत का परिवर्तन संविधान को स्वीकार किए जाने के साथ ही पूरा हुआ।

वंदे मातरम् और आत्मनिर्भरता का शंखनाद

इस वर्ष परेड की मुख्य थीम 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष और विकसित भारत' रही। समारोह की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद यूरोपीय संघ के दो दिग्गज नेताओं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, ने पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाई।

सैन्य शक्तिः स्वदेशी तकनीक का लोहा

भारतीय सेना ने इस बार अपनी

'आत्मनिर्भरता' का डंका बजाया। परेड में पहली बार स्वदेशी श्सूर्यास्त्रश रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, जो 300 किलोमीटर तक सटीक मार करने में सक्षम है।

- **ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन:** आसमान में राफेल, सुखोई-30 और मिग-29 विमानों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' फॉर्मेशन बनाकर भारत की रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति का परिचय दिया।
- **भैरव लाइट कमांडो:** नई गठित 'भैरव लाइट कमांडो बटालियन' के ऊंचे कदमताल ने दर्शकों में नया जोश भर दिया।
- **डिजिटल सैन्य दस्ता:** स्वदेशी प्लेटफॉर्म और संचार प्रणालियों से लैस 'फेज्ड बैटल एरे' ने आधुनिक युद्ध के प्रति भारत की तैयारियों को प्रदर्शित किया।

भारतीय नौसेना का प्रदर्शन:

'एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक मजबूत नौसेना' की थीम पर आधारित भारतीय नौसेना की झांकी में भारत की समुद्री यात्रा को दर्शाया गया, जिसमें पांचवीं शताब्दी के एक सिलाई जहाज (जिसे अब INSV कौंडिन्य नाम दिया गया है) से लेकर INS विक्रांत और INS उदयगिरि जैसे आधुनिक स्वदेशी प्लेटफार्मों तक, साथ ही INSV तारिणी के विश्व भ्रमण मार्ग को भी दिखाया गया।

नारी शक्ति: कर्तव्य पथ पर 'दुर्गा' का रूप

परेड का सबसे भावनात्मक और गौरव पूर्ण क्षण वह था जब 'नारी शक्ति' की गर्जना सुनाई दी। इस वर्ष की परेड में महिलाओं की भागीदारी केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी थी:

- गौरवशाली क्षण का प्रतीक बनीं इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान मौजूद रहीं। हरियाणा के झज्जर जिले के कासनी गांव की रहने वाली अक्षिता एक सामान्य परिवार से निकलकर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनीं। वहीं महिला सैनिकों ने मोटरसाइकिल पर बेहतरीन स्टंट ने दर्शकों का दिल जीता और महिला शक्ति किसी से कम नहीं का संदेश भी दिया।
- नारी नेतृत्व की एक और मिसाल बनीं सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट सिमरन बाला। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले की 26 वर्षीय सिमरन ने गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व कर इतिहास रच दिया। उनके नेतृत्व में 147 पुरुष सीआरपीएफ जवानों ने कदमताल की। यह पहली बार था जब किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस परेड में केवल पुरुषों की अर्द्धसैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। उनका यह नेतृत्व आत्मविश्वास और क्षमता का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा।
- इंडियन एयरफोर्स की मार्चिंग टुकड़ी में भी महिलाओं की मजबूत उपस्थिति दिखी। स्क्वाड्रन लीडर जगदीश कुमार के नेतृत्व में चल रही टुकड़ी में स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर चंद्रकार और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश आगे-आगे कदमताल करते नजर आए। इसके अलावा महिला जवानों ने मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

यूरोपीय संघ दल

पहली बार, ऑपरेशन अटलांटा और एस्पाइड्स के झंडे लिए हुए यूरोपीय संघ के एक सैन्य दल ने परेड में भाग लिया, जो यूरोप के बाहर किसी सैन्य परेड में यूरोपीय संघ की पहली उपस्थिति को

दर्शाता है।

इस बार गणतंत्र सिंगापुर में भी रहा खास:

- भारत का 77 वां गणतंत्र दिवस सिंगापुर में भी उत्साह से मनाया गया। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पाक एम्बुले ने समारोह का नेतृत्व किया। बडी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग आयोजन में शामिल हुए।
- सिंगापुर में भारतीय स्कूलो के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सारंग हेलिकॉप्टर दस्ते के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह दस्ता अगले सप्ताह सिंगापुर एयर शो में भाग लेगा।

झांकियों का वैभव: विरासत और विकास का संगम:

- **उत्तर प्रदेश:** इस झांकी के माध्यम से बुंदेलखंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया।
- **असम:** झांकी 'आशिरकंडी' नामक शिल्प गांव पर आधारित है, जो अपनी पारंपरिक कला को प्रदर्शित करती है।
- **छत्तीसगढ़:** यह झांकी स्वतंत्रता के मंत्र के रूप में वंदे मातरम के महत्व को दर्शाती है।
- **गुजरात:** मुख्य आकर्षण स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम है, जो राज्य की देशभक्ति की भावना को पेश करती है।
- **हिमाचल प्रदेश:** इस झांकी का विषय है कि हिमाचल प्रदेश न केवल देवभूमि है, बल्कि उतनी ही महान वीरभूमि भी है।
- **जम्मू और कश्मीर:** यहां की झांकी में केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और लोक नृत्यों की झलक देखने को मिली।

- **केरल:** यह झांकी वॉटर मेट्रो और 100% डिजिटल होने की उपलब्धि के माध्यम से आत्मनिर्भर केरल को प्रदर्शित करती है।
- **महाराष्ट्र:** यहां गणेशोत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया।
- **मणिपुर:** 'समृद्धि की ओर' विषय के साथ यह झांकी मणिपुर के उत्पादों की खेतों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक की यात्रा दर्शाती है।
- **नगालैंड:** यहां प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव के माध्यम से संस्कृति, पर्यटन और आत्मनिर्भरता का जश्न मनाया।
- **ओडिशा:** 'मिट्टी से सिलिकॉन तक' विषय के साथ यह झांकी परंपरा और नवाचार के संगम को प्रदर्शित करती है।
- **पुदुचेरी:** यह अपनी समृद्ध शिल्प कला, सांस्कृतिक विरासत और 'ऑरोविल' के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है।
- **राजस्थान:** यहां की झांकी में ऊंट की खाल पर की गई कलाकारी और स्वर्ण कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया।
- **तमिलनाडु:** यह राज्य खुद को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माण केंद्र के रूप में पेश करता है, जो समृद्धि का मंत्र है।
- **पश्चिम बंगाल:** यह झांकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है।
- **मध्य प्रदेश:** यह झांकी पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और योगदान को समर्पित है।
- **पंजाब:** यहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को श्रद्धा के साथ दिखाया गया।

77वां गणतंत्र दिवस इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकारी राष्ट्र बन चुका है। स्वदेशी तोपों की 21 सलामी और 'वंदे मातरम्' की गूंज के साथ, कर्तव्य पथ से उठी यह आवाज पूरी दुनिया को यह संदेश दे गई कि भारत अपनी विरासत को सहेजते हुए विकास के शिखर की ओर अग्रसर है।

पद्म सम्मान 2026:
गुमनाम नायकों की पहचान और प्रतिभा का राजकीय अभिनंदन

भारत रत्न के बाद देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान श्पद्म पुरस्कारोंश की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। यह केवल एक पदक या प्रमाण पत्र नहीं है, ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करना है। 1954 में अपनी स्थापना से लेकर 2026 तक, इन पुरस्कारों ने कई बदलाव देखे हैं, विशेषकर 'अभिजात्य वर्ग के सम्मान' से 'जनता के सम्मान' बनने तक का सफर।

ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल के आसपास होते हैं। वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों के प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिनमें 2 युगल पुरस्कार (युगल पुरस्कार को एक ही माना जाता है) शामिल हैं। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः कैसे हुई शुरुआत?

भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की थी, भारत रत्न और तीन-वर्गीय 'पद्म विभूषण' (पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग)।

- **नामों में बदलावः** 8 जनवरी, 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना के जरिए इनके नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिए गए।
- **निलंबन का दौरः** ये पुरस्कार हमेशा निर्बाध नहीं रहे। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इन्हें बंद कर दिया था, जिन्हें 1980 में इंदिरा गांधी

सरकार ने दोबारा शुरू किया। इसके बाद 1992 से 1995 के बीच कुछ कानूनी विवादों के कारण भी इनकी घोषणा नहीं हुई थी।

पुरस्कारों की श्रेणियां और गरिमा

श्रेणी	महत्व	पात्रता
पद्म विभूषण	दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान	असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए।
पद्म भूषण	तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान	उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए।
पद्म श्री	चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान	किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए

कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्ते

- **पदक, उपाधि नहीं:** सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, इन पुरस्कारों का उपयोग 'उपाधि' के रूप में नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता (जैसे 'पद्म श्री फलाने सिंह' लिखना गलत है)।
- **विजेताओं की संख्या:** एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर) 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **कोई नकद राशि नहीं:** इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद राशि नहीं दी जाती, बल्कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है।
- **पहनने का तरीका:** इन पदकों को गले में नहीं पहना जाता, बल्कि इन्हें बाएं सीने (Left Breast) पर एक रिबन की मदद से लगाया जाता है।

2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार:

- **पद्म विभूषण (5)**
  - स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत)- कला - महाराष्ट्र
  - श्री के टी थॉमस- सार्वजनिक मामले- केरल
  - सुश्री एन राजम-कला, वाराणसी उत्तर प्रदेश
  - श्री पी नारायणन-साहित्य एवं शिक्षा- केरल
  - स्वर्गीय वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत)-सार्वजनिक मामले-केरल
- **पद्म भूषण (13)**

पद्म भूषण विजेता	श्रेणी	स्थान
सुश्री अलका याग्निक	कला	महाराष्ट्र
श्री भगत सिंह कोश्यारी	सार्व. जनिक मामले	उत्तराखंड
श्री कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी	चिकित्सा	तमिलनाडु
श्री ममूटी	कला	केरल
डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु	चिकित्सा	संयुक्त राज्य अमेरिका
श्री पीयूष पांडे (मरणोपरांत)	कला	महाराष्ट्र
श्री एस के एम मैइलानंदन	सामा. जिक कार्य	तमिलनाडु
श्री शतावधानी आर गणेश	कला	कर्नाटक
श्री शिबू सोरेन (मरणोपरांत)	सार्व. जनिक मामले	झारखंड
श्री उदय कोटक	व्यापार और उद्योग	महाराष्ट्र
श्री वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत)	सार्व. जनिक मामले	दिल्ली
श्री वेल्लापल्ली नटेसन	सार्व. जनिक मामले	केरल
श्री विजय अमृतराज	खेल	संयुक्त राज्य अमेरिका

- **कुल 113 पद्म श्री दिए गए जिनमे 10 विजेता उत्तर प्रदेश से रहे-**

उत्तर प्रदेश के पद्म श्री विजेता	श्रेणी	स्थान
श्री अनिल कुमार रस्तोगी	कला	लखनऊ, उत्तर प्रदेश
श्री अशोक कुमार सिंह	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	गाजीपुर, उत्तर प्रदेश
श्री बुद्ध रश्मी मणि	पुरातत्व	बागपत, उत्तर प्रदेश
श्री चिरंजी लाल यादव	कला	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
श्री केवल कृष्ण ठकराल	चिकित्सा	लखनऊ, उत्तर प्रदेश
सुश्री मंगला कपूर	साहित्य और शिक्षा	वाराणसी, उत्तर प्रदेश
श्री प्रवीण कुमार-खेल	खेल	नोएडा, उत्तर प्रदेश

श्री रघुपत सिंह (मरणोपरांत)	कृषि	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
श्री राजेंद्र प्रसाद	चिकित्सा	बस्ती, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सुन्दर	चिकित्सा	वाराणसी, उत्तर प्रदेश

नोट - 2026 में उत्तर प्रदेश से 1 पद्म विभूषण (सुश्री एन राजम-कला) और 10 पद्म श्री विजेता रहे।

विदेशी पद्म पुरस्कार विजेता:

विदेशी पद्म विजेता	पु. रस्क. ार	श्रेणी	स्थान
डॉ. नोरी तात्रेयुडु	पद्म भूषण	चिकित्सा	संयुक्त राज्य अमेरिका
श्री विजय अमृतराज-	पद्म भूषण	खेल	संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोच	पद्म श्री	कला	जर्मनी
सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा	पद्म श्री	साहित्य और शिक्षा	रूस
श्री प्रतीक शर्मा	पद्म श्री	चिकित्सा	संयुक्त राज्य अमेरिका
श्री व्ला. दमीर मेस्ट. विरिश्विली (मरण ोपरांत)	पद्म श्री	खेल	जॉर्जिया

गुमनाम नायकों की जीत:

इस बार की सूची में उन चेहरों को प्रमुखता मिली है जो दशकों से समाज के अंतिम छोर पर बदलाव ला रहे हैं। सरकार ने 45 ऐसे व्यक्तियों को चुना है जिन्हें 'गुमनाम नायक' की श्रेणी में रखा गया है:

- **अंके गौड़ा (कर्नाटक:** कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने 20 लाख से अधिक पुस्तकों का श्पुस्तका मानेश नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फ्री-एक्सेस पुस्तकालय खड़ा कर दिया।
- **हल्ली वार (मेघालय:** पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले योद्धा।
- **तगा राम भील (राजस्थान):** राजस्थान के पारंपरिक वाद्य यंत्र 'अल्गोजा' को पुनर्जीवित करने वाले कलाकार।
- **डॉ. अरमिडा फर्नांडीज (महा. राष्ट्र):** एशिया का पहला 'ह्यूमन मिल्क बैंक' स्थापित करने वाली चिकित्सक।

खेल और कला का संगम

भारतीय क्रिकेट के 'हिटमैन' रोहित शर्मा और महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्म श्री से नवाजा जाना खेलों के प्रति देश के बढ़ते गौरव को दर्शाता है। वहीं, सिनेमा जगत के 'ही-मैन' धर्मेंद्र और दिग्गज अभिनेता ममूटी का सम्मान उनकी दशकों लंबी कला यात्रा का राजकीय अभिनंदन है।

2014 के बाद का 'पैराडाइम शिफ्ट': पीपुल्स पद्म

पिछले एक दशक में पद्म पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पहले जहाँ ये पुरस्कार अक्सर सिफारिशों और राजनीतिक रसूख पर आधारित माने जाते थे, वहीं अब 'Common Man' (आम आदमी) को केंद्र में रखा गया है।

- **ऑनलाइन नामांकन:** अब कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को ऑनलाइन नामांकित कर सकता है।
- **गुमनाम नायकों की खोज:** 2026 की सूची में शामिल 45 'Unsung Heroes' इसी बदलाव का नतीजा हैं। यह अब 'सिफारिशी तंत्र' से निकलकर 'खोज तंत्र' बन चुका है।

पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। अब यह सम्मान केवल लुटियंस दिल्ली के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुदूर गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और हाशिए पर खड़े उन लोगों तक पहुँच रहा है जिनकी साधना अब तक दुनिया की नजरों से ओझल थी। यह सही मायने में 'प्रतिभा का राजकीय अभिनंदन' है।

आईसीसी का वेन्यू बदलने से इनकार: बांग्लादेश टी 20 विश्व कप से बाहर, स्कॉटलैंड को मिली जगह

क्रिकेट की दुनिया में आज एक बड़ा भूचाल आ गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आगामी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की 'वेन्यू बदलने' या 'हाइब्रिड मॉडल' की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुरक्षा चिंताओं और प्रशासनिक अस्थिरता के कारण आईसीसी ने एक कड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और उनकी जगह स्कॉटलैंड को मुख्य ड्रॉ में शामिल किया गया है।

विवाद की जड़: क्या है पूरा मामला?

2026 टी20 विश्व कप की सह-मेजबानी भारत और बांग्लादेश को सौंपी गई थी। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने आईसीसी को चिंता में डाल दिया था।

- **बांग्लादेश की मांग:** बीसीबी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए अपने कुछ मैचों को तटस्थ स्थलों (Neutral Venues) पर कराने का प्रस्ताव दिया था।
- **आईसीसी का रुख:** आईसीसी ने स्पष्ट किया कि विश्व कप जैसे बड़े आयोजन के लिए लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडकास्टिंग अधिकार पहले से तय होते हैं। ऐन वक्त पर वेन्यू बदलना संभव नहीं है।

सुरक्षा ऑडिट और अंतिम

निर्णय:

- आईसीसी की सुरक्षा समिति ने जनवरी 2026 में बांग्लादेश के विभिन्न शहरों का दौरा किया था। सूत्रों के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ प्रमुख स्थलों को 'हाई-रिस्क' श्रेणी में रखा गया था।
- 'एक वैश्विक टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों और प्रशंसकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चूंकि मेजबान देश पूर्ण सुरक्षा गारंटी देने में असमर्थ रहा, इसलिए हमें वैकल्पिक योजना की ओर बढ़ना पड़ा।' - आईसीसी प्रवक्ता

स्कॉटलैंड की 'लॉटरी': कैसे मिली जगह?

बांग्लादेश के बाहर होने के बाद, आईसीसी ने 'नेक्स्ट बेस्ट टीम' (क्वालिफिकेशन रैंकिंग के आधार पर) को मौका देने का फैसला किया।

- **क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया:** स्कॉटलैंड, जो हालिया टी20 विश्व कप क्वालीफायर्स में बेहद करीब आकर चूक गई थी, रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर पहले स्थान पर थी।
- **ऐतिहासिक अवसर:** स्कॉटलैंड के लिए यह एक सुनहरा मौका है। बोर्ड ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे स्कॉटिश क्रिकेट के लिए एक 'नया सवेरा' बताया है।

बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा झटका:

यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के प्रशंसकों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है।

> **'एक वैश्विक टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों और प्रशंसकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। चूंकि मेजबान देश पूर्ण सुरक्षा गारंटी देने में असमर्थ रहा, इसलिए हमें वैकल्पिक योजना की ओर बढ़ना पड़ा।'**
>
> **- आईसीसी प्रवक्ता**

- **आर्थिक नुकसान:** मेजबानी छिनने और टूर्नामेंट से बाहर होने के कारण बीसीबी को करोड़ों डॉलर के राजस्व का घाटा होगा।
- **खिलाड़ियों की निराशा:** शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए यह संभवतः अंतिम टी20 विश्व कप था, जिसमें वे अब भाग नहीं ले पाएंगे।

भारत पर बढ़ेगा भार?

अब जबकि बांग्लादेश के हिस्से के मैच वहां नहीं होंगे, आईसीसी उन मैचों को भारत के विभिन्न शहरों में शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है।

- **नए वेन्यू:** बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता को अतिरिक्त मैचों की मेजबानी मिल सकती है।
- **शेड्यूल में बदलाव:** आईसीसी अगले 48 घंटों में नया और संशोधित शेड्यूल जारी कर सकता है।

आईसीसी का यह निर्णय सख्त जरूर है, लेकिन यह खेल के व्यवसायीकरण और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। बांग्लादेश के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि खेल और राजनीति के घालमेल ने उन्हें वैश्विक मंच पर कितना पीछे धकेल दिया है। वहीं, स्कॉटलैंड के 'अंडरडॉग्स' अब विश्व कप में अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं।

इंदौर की त्रासदी ने जल सुरक्षा पर खड़े किए गंभीर सवाल: क्या उत्तर प्रदेश भी है इसी खतरे के मुहाने पर

देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव रखने वाला इंदौर आज एक भयावह त्रासदी के साये में है। स्वच्छता के ऊंचे मानकों और 'वाटर प्लस' के तमगों के बीच, शहर की पाइपलाइनों में सीवेज का घुलना न केवल व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि यह भी बताता है कि प्रशासन की श्सतही चमकश के नीचे जमीनी हकीकत कितनी खोखली है।

इंदौर त्रासदी: क्या हुआ और क्यों?

दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह और जनवरी 2026 की शुरुआत में इंदौर के भागीरथपुरा और महू इलाकों में दूषित पानी पीने से एक के बाद एक कई मौतें हुई। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह आंकड़ा 25–26 तक पहुँच गया है, जबकि सरकारी ऑडिट में अब तक 15 मौतों की पुष्टि की गई है।

त्रासदी के मुख्य कारण:

- **सीवेज का मिश्रण:** जांच में पाया गया कि भागीरथपुरा में पेयजल की मुख्य पाइपलाइन एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजर रही थी। पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण सीवेज का पानी सीधे पीने के पानी में मिल गया।
- **प्रशासनिक लापरवाही:** कैग (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर में पाइपलाइन लीकेज की शिकायतों को दूर करने में 22 से 151 दिन तक का समय लगता है। भागीरथपुरा में भी नई पाइपलाइन का काम महीनों से अधर में लटका था।
- **बैक्टीरियल इन्फेक्शन:** पानी के

नमूनों में E- coli और अन्य घातक बैक्टीरिया पाए गए, जिससे लोगों को डायरिया, उल्टी और 'गुलेन-बैरे सिंड्रोम' (GBS) जैसी गंभीर बीमारियां हुईं।

उत्तर प्रदेश: खतरे की घंटी यहाँ भी कम नहीं

इंदौर की घटना ने उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है। यूपी में जल प्रदूषण की समस्या दोतरफा है-सतही जल (नदियां) और भूजल (Groundwater)।

महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण:

- **क्रॉस-कंटामिनेशन:** पुरानी शहरी बस्तियों में सीवेज और पेयजल की लाइनें एक-दूसरे के बेहद करीब होती हैं। पाइपलाइनों में दबाव कम होने पर 'सक्शन' (suction) पैदा होता है, जिससे बाहर का गंदा पानी रिसकर पाइप के अंदर चला जाता है।
- **नॉन-रेवेन्यू वाटर:** इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में आपूर्ति किया गया 65% से 70% पानी उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले ही लीकेज और चोरी के कारण नष्ट हो जाता है। यही लीकेज दूषित पानी के प्रवेश का मुख्य द्वार है।
- **जलजनित बीमारियों का बोझ:** डायरिया भारत में बाल मृत्यु दर का एक बड़ा कारण है। इंदौर की घटना में न केवल बच्चे, बल्कि वयस्क भी मल्टी-ऑर्गन फेल्योर और गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकारों का शिकार हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थिति:

- उत्तर प्रदेश में जल गुणवत्ता की स्थिति चिंताजनक है। नवीनतम आंकड़ों (2025-26) के अनुसार, राज्य के 75 में से 63 जिले ऐसे हैं जहाँ भूजल में हानिकारक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है।

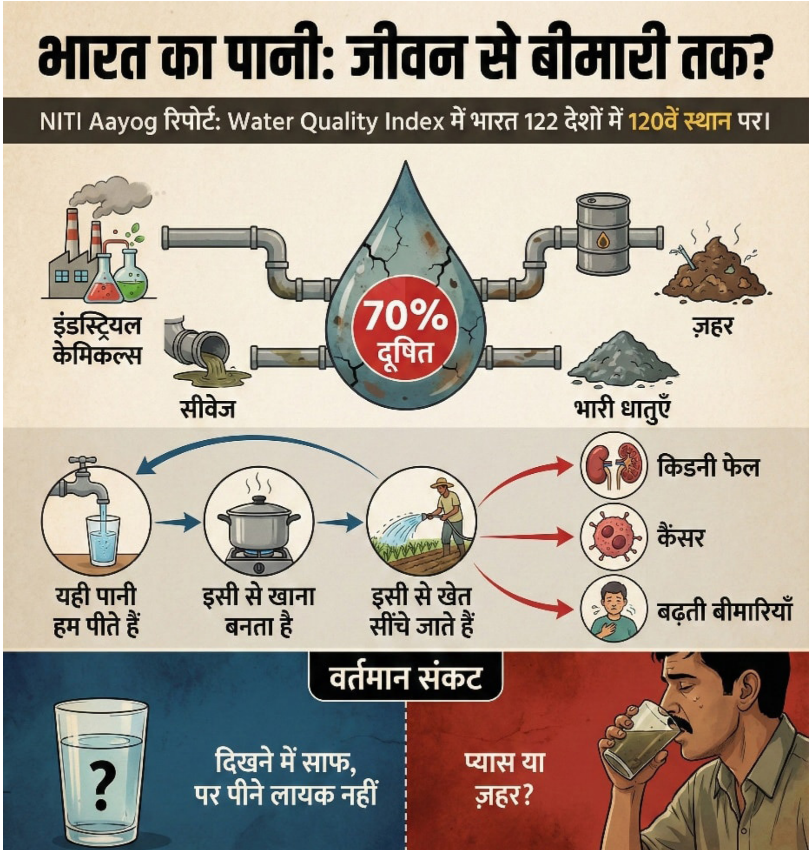

उत्तर प्रदेश: जल प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट का क्षेत्रीय विश्लेषण:

- **क्षेत्र:** पश्चिमी यूपी (हिंडन/काली नदी बेल्ट)
  - **समस्या का प्रकार:** औद्योगिक अपशिष्ट (भारी धातुएं/Heavy Metals)
  - **प्रमुख प्रभाव एवं प्रभावित जिले:** बागपत, मेरठ और सहारनपुर के कई गांवों में कैंसर, विकलांगता और गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां।
- **क्षेत्र:** पूर्वी यूपी (गंगा-घाघरा बेल्ट
  - **समस्या का प्रकार:** आर्सेनिक (Arsenic) प्रदूषण
  - **प्रमुख प्रभाव एवं प्रभावित जिले:** बलिया और गाजीपुर में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा WHO मानक से 5 गुना अधिक; त्वचा रोग और कैंसर का अत्यधिक खतरा।
- **क्षेत्र:** बुंदेलखंड एवं मध्य यूपी
  - **समस्या का प्रकार:** फ्लोराइड और नाइट्रेट
  - **प्रमुख प्रभाव एवं प्रभावित जिले:** दांतों और हड्डियों का समय से पहले कमजोर होना (Skeletal Fluorosis) और शिशुओं में 'ब्लू बेबी सिंड्रोम' की समस्या।

नीचे उन विशिष्ट जिलों की सूची दी गई है जहाँ पानी की गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है:

- **आर्सेनिक: प्रभावित जिले**
  - आर्सेनिक एक धीमा जहर है जो मुख्य रूप से गंगा और घाघरा नदियों के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे कैंसर और त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं।
  - **सर्वाधिक प्रभावित:** बलिया (सबसे खराब स्थिति), लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, और गोरखपुर।
  - **अन्य जिले:** बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या (फैजाबाद), सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, मऊ और शाहजहांपुर।
- **फ्लोराइड: प्रभावित जिले**
  - फ्लोराइड की अधिकता से दांतों और हड्डियों की गंभीर बीमारियां (फ्लोरोसिस) होती हैं। यूपी के लगभग 63 जिलों में यह समस्या है।
  - **सर्वाधिक प्रभावित:** उन्नाव, सोनभद्र, झांसी और मथुरा।
  - **अन्य जिले:** आगरा, अलीगढ़, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर नगर, फतेहपुर और हमीरपुर।
- **भारी धातुओं और नाइट्रेट से प्रभावित जिले:** औद्योगिक कचरे और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण इन जिलों का पानी पीने योग्य नहीं रहा:
  - **कानपुर और गाजियाबाद:** यहाँ पानी में क्रोमियम (Chromium) और सीसा (Lead) जैसे जहरीले तत्व पाए गए हैं।
  - **मेरठ और बागपत:** हिंडन नदी के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ का भूजल रासायनिक कचरे से भरा हुआ है।
  - **आगरा:** यहाँ नाइट्रेट और खारेपन (TDS) की समस्या सबसे अधिक है।

प्रदूषकों के आधार पर जिलों का वर्गीकरण:

प्रदूषक	मुख्य प्रभावित जिले	संभावित स्वास्थ्य जोखिम
आर्सेनिक	बलिया, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, गाजीपुर	कैंसर, त्वचा पर घाव (Skin Lesions), ब्लैकफुट डिजीज।
फ्लोराइड	उन्नाव, सोनभद्र, आगरा, मथुरा	हड्डियों का टेढ़ापन (Skeletal Fluoro-sis), दांतों का पीला होना।
नाइट्रेट / TDS	आगरा, मथुरा, प्रयागराज, अलीगढ़	ब्लू बेबी सिंड्रोम, गुर्दे (Kidney) की गंभीर समस्याएं।
भारी धातुएं	कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी	लिवर डैमेज, न्यू. रोलॉजिकल विकार (मस्तिष्क संबंधी बीमारियां)।

निष्कर्ष और समाधान

स्वच्छता का मतलब सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, बल्कि नलों से आने वाले पानी की शुद्धता भी है। जब तक 'वाटर ऑडिट' और 'पाइपलाइन हेल्थ चेकअप' को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, इंदौर जैसी त्रासदियां होती रहेंगी।

सरकार को प्रत्येक जिले में जल गुणवत्ता का रीयल-टाइम डैशबोर्ड बनाना चाहिए और सीवेज लाइनों को पेयजल आपूर्ति से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर रखना अनिवार्य करना चाहिए।

लोकतंत्र का मुखौटा और विस्तारवाद का चेहरा: अमेरिका की नई वैश्विक चालें

21वीं सदी के तीसरे दशक में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ 'लोकतंत्र की रक्षा' का नारा अब विस्तारवाद का पर्याय बनता जा रहा है। 26 जनवरी 2026 तक की वैश्विक हलचलें गवाह हैं कि अमेरिका अपनी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत संप्रभुता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को दरकिनार करने पर आमादा है। वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप और ग्रीनलैंड को हथियाने की जिद ने लोकतंत्र की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

वेनेजुएला: 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' और लोकतंत्र का हनन

- 3 जनवरी, 2026 की सुबह दुनिया ने एक चौंकाने वाली खबर सुनी। अमेरिका ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया।
- अमेरिका ने मादुरो पर 'नार्को-टेररिज्म' का आरोप लगाया है, लेकिन वैश्विक जानकारों का मानना है कि असली निशाना वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार और उसकी चरमराई हुई रिफाइनरियों पर कब्जा करना है।
- हालांकि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर घोषणा की है कि जब तक वेनेजुएला का तेल बुनियादी ढांचा फिर से खड़ा नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका वहां का शासन चलाएगा। यह सीधे तौर पर एक संप्रभु राष्ट्र पर औपनिवेशिक कब्जे जैसा है।

ग्रीनलैंड: व्यापारिक सौदा या सामरिक जबरदस्ती?

- वेनेजुएला के बाद अमेरिका की नजर अब उत्तर में स्थित ग्रीनलैंड पर है,

जो डेनमार्क का एक स्वायत्त हिस्सा है। जनवरी 2026 के मध्य तक ट्रंप प्रशासन ने डेनमार्क पर ग्रीनलैंड बेचने का भारी दबाव बनाया।

- **धमकी और यू-टर्न:** 9 जनवरी को ट्रंप ने कहा था कि यदि सौदा 'सीधे तरीके' से नहीं हुआ, तो वे इसे 'कठिन तरीके' (Hard Way) से करेंगे, जिससे सैन्य हस्तक्षेप का अंदेशा बढ़ा। हालांकि, 21 जनवरी को दावोस (WEF) में उन्होंने सैन्य बल के उपयोग से पीछे हटने का संकेत दिया, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों की तलवार अब भी लटकी है।
- **रणनीतिक कारण:** अमेरिका वहां अपना 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है ताकि रूस और चीन की आर्कटिक गतिविधियों पर लगाम कसी जा सके।

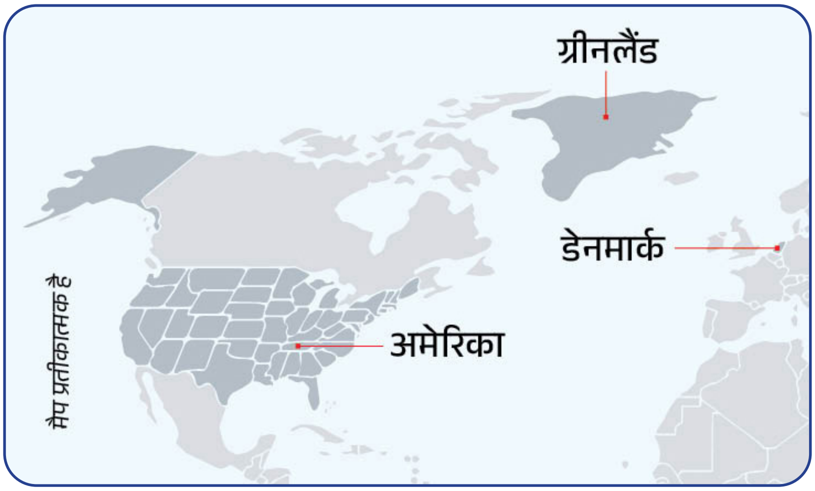

वैश्विक राजनीति पर असर: एक विश्लेषण

अमेरिकी कदमों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने 'नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था' (Rules-based Order) को हिला कर रख दिया है।

- **NATO में दरार:** डेनमार्क एक NATO सहयोगी है। अपने ही सहयोगी की जमीन पर कब्जा करने की धमकी ने नाटो के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। यूरोपीय संघ (EU) अब अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' की बात कर रहा है।
- **चीन-रूस का उदय:** अमेरिका के इस आक्रामक रुख ने ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) को चीन और रूस के और करीब धकेल दिया है। ब्रिक्स (BRICS) जैसे संगठन अब अमेरिकी डॉलर और उसके प्रभुत्व के खिलाफ अधिक मुखर हो रहे हैं।
- **लोकतंत्र की विश्वसनीयता:** जब अमेरिका अपनी मर्जी से चुनी हुई सरकारों को गिराता है, तो वह दुनिया भर में अधिनायकवादी ताकतों को शह देता है। यह संदेश जाता है कि 'शक्ति ही सत्य है'।

भारत पर प्रभाव:

भारत के लिए यह स्थिति 'दोधारी तलवार' जैसी है। एक तरफ अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी जरूरी है, तो दूसरी तरफ संप्रभुता के सिद्धांतों पर समझौता करना भारत की पारंपरिक विदेश नीति के खिलाफ है।

भारत आर्थिक प्रभावः

- **क्षेत्रः** ऊर्जा सुरक्षा
  - **प्रभाव का स्तरः** सीमित
  - **मुख्य कारणः** भारत ने 2019 के बाद से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से वेनेजुएला से तेल आयात घटाकर कुल आयात का मात्र 0.3% कर दिया था।
- **क्षेत्रः** शेयर बाजार
  - **प्रभाव का स्तरः** अस्थिर
  - **मुख्य कारणः** भारतीय ओएमसी (OMCs) जैसे ONGC और रिलायंस के शेयरों में उतार-चढ़ाव, क्योंकि वेनेजुएला में पुराने निवेश और 'ऑयल-फॉर-डीजल' सौदों पर अनिश्चितता है।
- **क्षेत्रः** महंगाई
  - **प्रभाव** का स्तरः मध्यम
  - **मुख्य कारणः** यदि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल पार करती हैं, तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई महंगी होगी।
- भारत सरकार (MEA) ने 4 जनवरी 2026 को जारी अपने आधिकारिक बयान में 'गहरी चिंता' (Deep Concern) व्यक्त की है।
- **संतुलन की राजनीतिः** भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका की निंदा नहीं की है, लेकिन 'हिंसा के अंत' और 'शांतिपूर्ण संवाद' की अपील की है। यह भारत की उस मजबूरी को दर्शाता है जहाँ उसे एक तरफ ट्रंप प्रशासन के साथ प्रगाढ़ होते रक्षा संबंधों को बचाना है, तो दूसरी तरफ संप्रभुता के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का समर्थन करना है।
- **विपक्ष का हमलाः** कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसे 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन' बताते हुए मोदी सरकार की 'चुप्पी' पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर इस 'औपनिवेशिक मानसिकता' का विरोध करना चाहिए।

विस्तारवाद का अर्थशास्त्र

- **वैश्विक तेल बाजारः $50 का लक्ष्य बनाम 'सप्लाई शॉक'**: वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार (लगभग 303 अरब बैरल) का स्वामी है। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद तेल की कीमतों में एक अनोखा विरोधाभास देखा जा रहा हैः
  - **तत्काल प्रतिक्रियाः** 3 जनवरी को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद WTI क्रूड में 2.6% का उछाल आया। लेकिन, जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों द्वारा वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की घोषणा की, बाजार में कीमतों के गिरने की उम्मीद जगी।
  - **अमेरिका का मास्टर प्लानः** ट्रंप का लक्ष्य तेल की कीमतों को $50 प्रति बैरल तक लाना है ताकि अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत मिले और रूस-OPEC के गठबंधन को कमजोर किया जा सके।
  - **बाजार की स्थितिः** फिलहाल ब्रेंट क्रूड $60-$62 के दायरे में झूल रहा है। निवेशकों को डर है कि अल्पावधि में सप्लाई बाधित होगी, लेकिन दीर्घावधि में वेनेजुएला का तेल बाजार में आने से 'सप्लाई ग्लट' (अत्यधिक आपूर्ति) की स्थिति पैदा हो सकती है।
- **वैश्विक शेयर बाजार और 'सेफ हेवन' की ओर दौड़ः** अनिश्चितता के इस दौर में वैश्विक निवेशकों ने जोखिम भरे शेयरों से हाथ खींचना शुरू कर दिया हैः
  - **शेयर बाजारः** एशियाई बाजारों (निक्केई और हैंगसेंग) में गिरावट देखी गई है, जबकि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों (जैसे Chevron और ExxonMobil) के शेयरों में 'वेनेजुएला प्रोजेक्ट' की उम्मीद में उछाल आया है।
  - **सुरक्षित निवेशः** अनिश्चितता के चलते सोना (Gold) $4,400 प्रति औंस के पार निकल गया है। वहीं, डिजिटल गोल्ड के रूप में बिटकॉइन $94,000 के स्तर को छू चुका है।

यदि 2026 में भी दुनिया 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के सिद्धांत पर चलेगी, तो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अमेरिका को समझना होगा कि लोकतंत्र थोपा नहीं जाता, बल्कि उसका सम्मान किया जाता है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026: विनाश पर सृजन की विजय का सहस्राब्दी उत्सव

जनवरी 1026 में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर पहला बड़ा हमला कर भारत की आस्था को चोट पहुँचाने का प्रयास किया था। ठीक 1000 वर्ष बाद, जनवरी 2026 में भारत ने उसी स्थान पर 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' मनाकर दुनिया को संदेश दिया कि 'आतंक के बादल छंट जाते हैं, लेकिन आस्था का सूर्य सदैव देदीप्यमान रहता है।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित यह चार दिवसीय पर्व (8–11 जनवरी) भारत के 'सांस्कृतिक पुनर्जागरण' का प्रतीक बनकर उभरा।

पर्व का दोहरा महत्व: 1000 वर्ष का संघर्ष और 75 वर्ष का गौरव

प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर्व को दो महत्वपूर्ण मील के पत्थरों का संगम बताया:

- **विनाश के 1000 वर्ष:** 1026 ई. के प्रथम बर्बर आक्रमण की स्मृति में, यह उत्सव उन वीर योद्धाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने सदियों तक इस मंदिर की रक्षा की।
- **पुनर्निर्माण के 75 वर्ष:** वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा वर्तमान मंदिर के लोकार्पण के 75 वर्ष (हीरक जयंती) भी 2026 में पूरे हुए।

प्रधानमंत्री मोदी का स्वाभिमान कार्यक्रम:

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में स्वयं इन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया:

- **72 घंटे का अखंड 'ओंकार' नाद:** 10 जनवरी की रात, पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में चल रहे 72 घंटे के अखंड प्रणव अक्षर (ओंकार) मंत्र जाप के समापन सत्र में भाग लिया। उन्होंने गर्भगृह में विशेष पूजा-अर्चना की और महादेव का जलाभिषेक किया। इस मंत्रोच्चार की गूँज ने पूरे प्रभास पाटन को एक दिव्य ऊर्जा से भर दिया।
- **आधुनिक तकनीक से इतिहास का चित्रण: भव्य ड्रोन शो:** रात के समय सोमनाथ के आकाश में 3,000 से अधिक ड्रोन्स के माध्यम से एक अभूतपूर्व प्रकाश शो (Drone Show) का आयोजन किया गया। ड्रोन्स ने

आसमान में:

- ➢ गजनवी के हमले और मंदिर के टूटने के दृश्य बनाए।
- ➢ सरदार पटेल के पुनर्निर्माण के संकल्प को दर्शाया।
- ➢ अंत में 'विकसित भारत' और 'सोमनाथ की पताका' को प्रदर्शित कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया।

- **शौर्य यात्रा: वीरों को नमन:** 11 जनवरी की सुबह, प्रधानमंत्री ने 'शौर्य यात्रा' का नेतृत्व किया। इस यात्रा में 108 घोड़ों का एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो उन अनगिनत ज्ञात और अज्ञात योद्धाओं का प्रतीक था जिन्होंने मंदिर की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए थे।

प्रधानमंत्री का संबोधन: 'सृजन का मार्ग ही स्थायी है'

सोमनाथ की पावन धरा से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं:

- **आतंक बनाम आस्था:** उन्होंने कहा कि 'आतंकवादी और आक्रांता इतिहास के पन्नों में धूल बन गए, जबकि सोमनाथ आज भी अडिग खड़ा है। यह इस बात का प्रमाण है कि विनाश की शक्ति से सृजन की शक्ति हमेशा बड़ी होती है।'
- **विरासत और विकास:** उन्होंने जोर दिया कि भारत अब अपनी विरासत पर गर्व करने वाला देश है। उन्होंने 2026 के इस पर्व को 'गुलामी की मानसिकता से मुक्ति' का एक बड़ा अध्याय बताया।
- **आर्थिक संकल्प:** पीएम ने सोमनाथ की ऊर्जा को 'तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था' और 'विकसित भारत 2047' के संकल्पों से जोड़ा।

बुनियादी ढांचा और भविष्य का विजन:

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया:

- **सोमनाथ 3D इमर्सिव म्यूजियम:** एक ऐसा संग्रहालय जहाँ श्रद्धालु वर्चुअल रियलिटी (VR) के जरिए 10वीं शताब्दी के सोमनाथ का अनुभव कर सकते हैं।
- **सोमनाथ-गिर टूरिज्म सर्किट:** सोमनाथ मंदिर और गिर के शेरों को जोड़ने वाले एक विशेष पर्यटन कॉरिडोर की घोषणा की गई।
- **डिजिटल तीर्थ:** विश्वभर के शिव भक्तों के लिए AI-आधारित 'सोमनाथ सेवा ऐप' लॉन्च किया गया।

क्यों महत्वपूर्ण है 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व'?

यह पर्व केवल गुजरात का उत्सव नहीं था, बल्कि इसके गहरे कूटनीतिक और सामाजिक मायने थे:

- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद:** राम मंदिर के बाद सोमनाथ का यह भव्य उत्सव भारत के 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' को नई दिशा देता है।
- **ऐतिहासिक शुद्धि:** 1000 साल पुराने घावों को 'हार' के रूप में नहीं, बल्कि 'अजेय साहस' के रूप में मनाकर सरकार ने राष्ट्रीय मनोबल को ऊँचा किया है।
- **पर्यटन का नया हब:** इन आयोजनों से सोमनाथ में वार्षिक श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 करोड़ पार करने का अनुमान है, जिससे स्थानीय रोजगार में भारी वृद्धि होगी।

इस मंदिर की विशेषता 150 फुट का शिखर, 1666 स्वर्ण मंडित कलश और 14200 ध्वज हैं। प्रत्येक वर्ष 92-97 लाख श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं।

सोमनाथ में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका है। मंदिर के 906 कर्मियों में से 262 महिलाएं हैं। वे बिल्व वन, प्रसाद वितरण और मंदिर भोज सेवाओं का प्रबंध देखती हैं।

सोमनाथ मंदिर के बारे में:

- सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग

है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के उत्थान-पतन और हिंदू धर्म के अटूट पुनरुत्थान का प्रतीक है।

वास्तुकला की विशेषताएं

वर्तमान मंदिर 'कैलाश महामेरु प्रासाद' शैली (चालुक्य या सोलंकी शैली) में बना है।

- **शिखर:** इसकी ऊंचाई 155 फीट है, जिसके ऊपर 37 फीट लंबा ध्वज दंड है।
- **गर्भगृह:** मुख्य मंदिर में भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है।
- **बाण स्तंभ:** मंदिर परिसर में एक प्राचीन स्तंभ है जिसे 'बाण स्तंभ' कहते हैं। इस पर लिखा है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव (Antarctica) तक समुद्र के बीच में कोई भी भू-भाग नहीं है। यह प्राचीन भारतीय भूगोल के ज्ञान का बेजोड़ उदाहरण है।
- इस मंदिर की विशेषता 150 फुट का शिखर, 1666 स्वर्ण मंडित कलश और 14200 ध्वज हैं।
- प्रत्येक वर्ष 92-97 लाख श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं।
- सोमनाथ में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका है। मंदिर के 906 कर्मियों में से 262 महिलाएं हैं। वे बिल्व वन, प्रसाद वितरण और मंदिर भोज सेवाओं का प्रबंध देखती हैं।
- सोमनाथ मंदिर न्यास में 363 महिलाएं कार्यरत हैं। वार्षिक 9 करोड़ रुपए की आय वाला यह न्यास महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहा है।

पौराणिक कथा

- मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रदेव (सोम) ने की थी।

कथा के अनुसार, राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने और अपना क्षय रोग दूर करने के लिए चंद्रमा ने इसी स्थान पर शिव की आराधना की थी। शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया, इसीलिए उन्हें 'सोमनाथ' (चंद्रमा के स्वामी) कहा जाता है।

स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण

- भारत की स्वतंत्रता के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ।
- सरदार वल्लभभाई पटेल ने पुनर्निर्माण का निर्णय लिया।
- 1951 में मंदिर का उद्घाटन हुआ– उद्घाटन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने किया।
- यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2026 में मनाया गया 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' भारत के उस अटूट भरोसे का प्रतीक है कि 'सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता।' यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि भारत की जड़ें कितनी गहरी हैं और उसका भविष्य कितना उज्ज्वल।

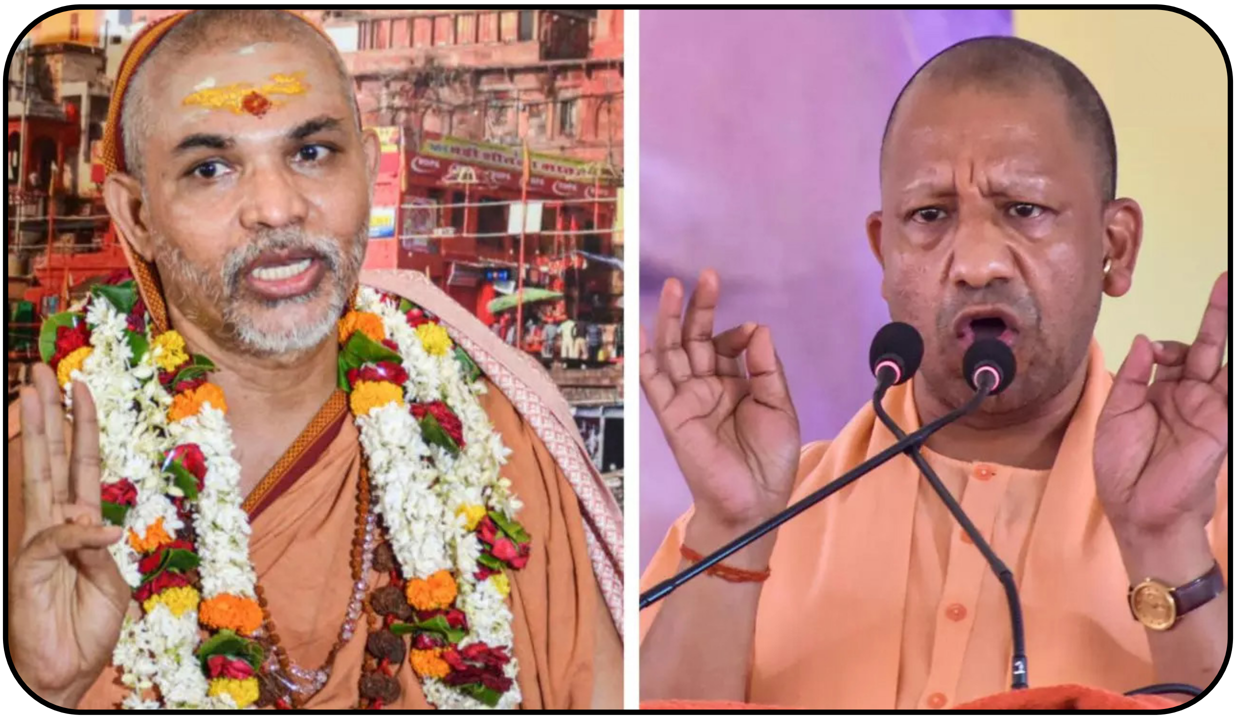

मर्यादा, न्याय और विवादः शंकराचार्य बनाम यूपी सरकार मामले की जमीनी हकीकत

जनवरी 2026 का माघ मेला प्रयागराज की रेती पर केवल आध्यात्मिक स्नान का साक्षी नहीं बना, बल्कि इसने 'धर्मदंड' और 'राजदंड' के बीच एक ऐसा टकराव देखा जिसने देशव्यापी बहस छेड़ दी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुआ यह विवाद अब कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक नई शक्ल अख्तियार कर चुका है।

विवाद की चिंगारीः 18 जनवरी 2026 (मौनी अमावस्या)

विवाद की शुरुआत मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हुई।

- **घटनाः** स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ पालकी (चतुष्पथ) पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे।
- **प्रशासनिक रोकः** अत्यधिक भीड़ का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें वीआईपी मार्ग पर जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और शंकराचार्य के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई।
- **आरोपः** स्वामी जी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी की और उनकी 'शिखा' (चोटी) पकड़कर खींची, जिसे उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करार दिया।

प्रशासन का पलटवारः 'शंकराचार्य' पद पर सवाल

जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरने पर बैठकर माफी की मांग की, तब प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने विवाद को और गरमा दियाः

- **नोटिस की राजनीतिः** प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी जी को

नोटिस जारी कर उनसे 'शंकराचार्य' होने का प्रमाण मांग लिया। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने स्थगन आदेश का हवाला देते हुए उनके पद के इस्तेमाल पर स्पष्टीकरण मांगा।

- **उमा भारती का रुख:** भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने अपनी ही सरकार के प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा, 'शंकराचार्य से सबूत मांगना प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन है।'

ब्यूरोक्रेसी में बगावत: अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा

- इस विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
- **वजह:** उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि संतों के साथ हुआ दुर्व्यवहार और सरकार की 'ब्राह्मण विरोधी' मानसिकता को वे सहन नहीं कर सकते।
- **परिणाम:** सरकार ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया और उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए, लेकिन इस घटना ने ब्यूरोक्रेसी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी।

40 दिन का अल्टीमेटम: 'राजमाता' गाय का मुद्दा

विवाद केवल स्नान तक सीमित नहीं रहा। 30 जनवरी 2026 को वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी:

- **अल्टीमेटम:** उन्होंने सरकार को 40 दिन का समय दिया कि वे गाय को 'राजमाता' घोषित करें और बीफ एक्सपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं।
- **चेतावनी:** 'यदि मांगें पूरी नहीं हुई, तो 11 मार्च 2026 को हजारों संतों के साथ लखनऊ में महा–आंदोलन होगा।'

यह विवाद केवल एक संत और एक मुख्यमंत्री के बीच का नहीं है। यह शास्त्र और शासन के बीच की वह लकीर है जो अक्सर धुंधली हो जाती है। जहाँ सरकार इसे 'व्यवस्था और कानून' का मामला बता रही है, वहीं संत समाज इसे 'धार्मिक स्वायत्तता' पर हमला मान रहा है। 11 मार्च को लखनऊ में होने वाला प्रस्तावित 'संत समागम' तय करेगा कि यह गौरवगाथा किस दिशा में मुड़ेगी।

"हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता. हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर जहां-तहां वातावरण ख़राब नहीं कर सकता. उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा.

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

"परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना, शाब्दिक हिंसा है और पाप भी. ऐसा कहने वाले के साथ-साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेज़ें थपथपाई हैं.

अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री

स्वाद से समृद्धि तक: UP की 'एक जनपद, एक व्यंजन' योजना

उत्तर प्रदेश, जिसने 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ODOP) के माध्यम से कुटीर उद्योगों की वैश्विक ब्रांडिंग कर एक मिसाल कायम की थी, अब अपनी इसी सफलता को रसोई की थाली तक ले आया है। 24 जनवरी 2026 को 'यूपी दिवस' के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक रूप से 'एक जनपद-एक व्यंजन' (One District One Cuisine - ODOC) योजना का आगाज किया। यह केवल स्वाद का विस्तार नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जोड़ने की एक दूरगामी रणनीति है।

पृष्ठभूमि: क्यों है ऐसी योजना की आवश्यकता?

- ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के हर जिले की अपनी एक 'स्वाद पहचान' रही है, चाहे वह मथुरा का पेड़ा हो, आगरा का पेठा या फिर जौनपुर की इमरती। लेकिन, ये व्यंजन अक्सर स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहे। हाल के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 15% वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जिसे भुनाने के लिए सरकार ने व्क्व्च की तर्ज पर व्यंजनों के मानकीकरण का निर्णय लिया है।

योजना के मुख्य स्तंभ: कैसे काम करेगा ODOC?

सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए चार प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है:

- **जीआई टैगिंग (GI Tagging):** विशिष्ट व्यंजनों को भौगोलिक संकेत (GI Tag) दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि उनकी मौलिकता और अंतरराष्ट्रीय पहचान सुरक्षित रहे।
- **हाइजीन और स्टैंडर्डाइजेशन:** 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) के साथ मिलकर स्थानीय हलवाइयों और रसोइयों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि स्वाद के साथ शुद्धता का वैश्विक मानक बना रहे।
- **पाककला पर्यटन (ब्नसपदंतल ज्वनतपेउ):** पर्यटन विभाग 'फूड सर्किट' विकसित कर रहा है। उदाहरण के लिए, लखनऊ-कानपुर-अयोध्या बेल्ट को 'अवध स्वाद मार्ग' के रूप में प्रमोट किया जाएगा।
- **पैकेजिंग और एक्सपोर्ट:** ODOP की तरह ही व्यंजनों की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने के लिए आधुनिक पैकेजिंग

तकनीक पर सब्सिडी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के 'स्वाद मानचित्र' की एक झलक

योजना के तहत चिन्हित कुछ प्रमुख व्यंजन और उनके जिले:

जनपद	चयनित विशिष्ट व्यंजन	विशेषता
लखनऊ	नवाबी टुंडे कबाव	गलौटी कबाब की वैश्विक ख्याति
मथुरा	मथुरा का पेड़ा	शुद्ध खोये और परंपरा का संगम
वाराणसी	बनारसी	सुब. ह–ए–बना. रस की सांस्कृतिक पहचान
प्रयागराज	अमरुद की सुर्खी (जेली/ बर्फी)	इलाहाबादी सफेदा और सुर्खी की मिठास
सिद्धार्थनगर	काला नमक चावल (पुलाव)	बुद्ध का महाप्रसाद, बेहतरीन खुशबू
आगरा	आगरा का पेठा	कद्दू से बनी विश्व प्रसिद्ध मिठाई

आर्थिक प्रभावः समृद्धि का नया स्वाद

'एक जनपद–एक व्यंजन' योजना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि जेब भरने के लिए भी है:

- **रोजगार सृजन:** स्थानीय रसोइयों, कैटरर्स और पैकेजिंग यूनिट्स के माध्यम से राज्य में लगभग 5 लाख नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
- **महिला सशक्तिकरण:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अचार, पापड़ और स्थानीय स्नैक्स के निर्माण और मार्केटिंग के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- **कृषि को बढ़ावा:** जब किसी जिले का विशिष्ट व्यंजन मशहूर होगा, तो वहां की फसलों (जैसे विशेष किस्म के चावल, दाल या मसालों) की मांग सीधे तौर पर बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी।

थाली से वैश्विक बाजार तक:

- उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना राज्य की 'सॉफ्ट पावर' को दुनिया के सामने रखने का एक अनूठा तरीका है। यदि यह योजना अपनी पूरी क्षमता से लागू होती है, तो वह दिन दूर नहीं जब पेरिस और न्यूयॉर्क के कैफे में 'काला नमक चावल का पुलाव' या 'अवधी कोरमा' उसी शान से परोसा जाएगा जैसे इटैलियन पास्ता या जापानी सुशी।

'स्वाद से समृद्धि तक' का यह सफर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक 'जायकेदार' कदम साबित होगा।

बुढ़ापे का मजबूत सहाराः 2031 तक जारी रहेगी अटल पेंशन योजना

जानिए आपके लिए इसके क्या हैं मायने

असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों और निम्न-आय वर्ग के परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को अगले पांच वर्षों यानी वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय न केवल योजना की निरंतरता सुनिश्चित करता है, बल्कि देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

क्या है कैबिनेट का फैसला?

सरकार ने इस योजना को 2031 तक बढ़ाने के साथ-साथ इसके प्रचार-प्रसार और 'गैप फंडिंग' (वित्तीय कमी को पूरा करने) के लिए भी बजटीय सहायता जारी रखने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन श्रमिकों तक पहुँचना है जो अब भी किसी भी प्रकार की औपचारिक पेंशन व्यवस्था से बाहर हैं।

अटल पेंशन योजनाः एक नजर में

9 मई 2015 को शुरू की गई यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आयकर दाता नहीं हैं और बुढ़ापे में नियमित आय की चिंता में रहते हैं। 19 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं।

योजना की प्रमुख विशेषताएंः

- **निश्चित पेंशनः** 60 वर्ष की आयु के बाद रू.1,000 से लेकर रू.5,000 तक की मासिक पेंशन की गारंटी।
- **योगदान की अवधिः** योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- **सुरक्षा का चक्रः** अंशधारक की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी। दोनों की मृत्यु के बाद, जमा की गई पूरी राशि (कॉर्पस) नामांकित व्यक्ति (Nominee) को लौटा दी जाती है।

निवेश और लाभ का गणितः

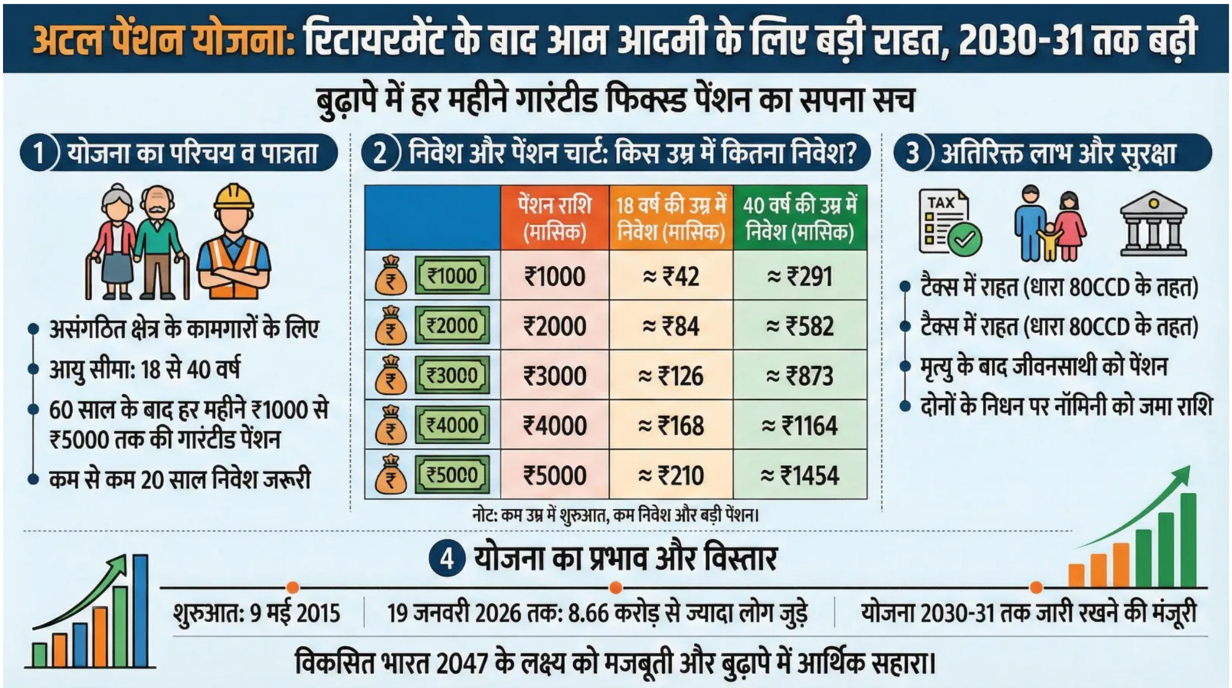

अटल पेंशन योजना की सबसे बड़ी खूबी इसकी सुगमता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 18 वर्ष का युवा रू. 5,000 की मासिक पेंशन का विकल्प चुनता है, तो उसे हर महीने मात्र रू. 210 का योगदान देना होगा।

प्रवेश की आयु	योगदान की अवधि	मासिक योगदान (रूपये 5,000 पेंशन के लिए)	नॉमिनी को मिलने वाली राशि
18 वर्ष	42 वर्ष	रू. 210	रू. 8.5 लाख
25 वर्ष	35 वर्ष	रू. 376	रू.8.5 लाख
35 वर्ष	25 वर्ष	रू. 902	रू.8.5 लाख
40 वर्ष	20 वर्ष	रू. 1,454	रू.8.5 लाख

विस्तार क्यों है जरूरी?

भारत की एक बड़ी आबादी आज भी असंगठित क्षेत्र (दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू सहायक) में कार्यरत है। 2031 तक योजना का विस्तार 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक के पास एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति (Retirement) का विकल्प भी होना चाहिए।

बॉर्डर 2: लोंगेवाला से आगे, अब बसंतर के मैदानों में गूंजेगी वीरता की हुंकार

भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी देशभक्ति और युद्ध पर आधारित फिल्मों की बात होती है, 'बॉर्डर' (1997) का नाम सबसे पहले आता है। अब करीब तीन दशक बाद, जे.पी. दत्ता की उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 'बॉर्डर 2' तैयार है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ लोंगेवाला की चौकियों तक सीमित नहीं है; यह फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध के उन पन्नों को पलटने जा रही है, जो शौर्य और रणनीति की पराकाष्ठा थे।

रेगिस्तान से लेकर नदियों तक: युद्ध का नया मोर्चा

'बॉर्डर 2' केवल एक सीक्वल नहीं, बल्कि 1971 के युद्ध के उन महत्वपूर्ण मोर्चों का चित्रण है जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। फिल्म के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाएं होने वाली हैं:

- **बैटल ऑफ बसंतर (Battle of Basantar):** इसे भारतीय सेना के सबसे भीषण टैंक युद्धों में से एक माना जाता है। शकरगढ़ सेक्टर में लड़ी गई इस लड़ाई ने साबित कर दिया था कि भारतीय जांबाज न केवल जमीन पर, बल्कि फौलादी टैंकों के साथ भी दुश्मन को धूल चटाने में माहिर हैं।
- **ऑपरेशन चंगेज खान (Operation Chengiz Khan):** फिल्म उस रणनीतिक मोड़ को भी दिखाएगी जब पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला कर युद्ध की शुरुआत की थी। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच का जो तालमेल दिखा, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

साहस, बलिदान और सामरिक कौशल

जहाँ पहली फिल्म 'होल्डिंग ग्राउंड' (अपनी जगह बचाए रखने) की कहानी थी, वहीं 'बॉर्डर 2' आक्रामक रणनीति और बलिदान पर केंद्रित है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे भारतीय जनरलों ने 'ऑपरेशन चंगेज खान' के बाद अपनी चालें चलीं और बसंतर के मैदानों में दुश्मन के 'पैटन टैंकों' को कब्रिस्तान में बदल दिया।

क्यों खास होगी 'बॉर्डर 2'?

- **अत्याधुनिक तकनीक:** पुराने दौर की भावुकता के साथ-साथ इस बार आधुनिक VFX और सिनेमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि युद्ध के दृश्यों को वैश्विक स्तर का बनाया जा सके।
- **मल्टी-स्टारर कास्ट:** फिल्म में सनी देओल के साथ नई पीढ़ी के सितारों का संगम देखने को मिलेगा, जो युवाओं को इतिहास से जोड़ने का काम करेगा।
- **संगीत और जज्बा:** 'संदेशे आते हैं' जैसा जादू दोबारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो हर भारतीय के दिल में राष्ट्रवाद की लौ जला सके।
- **संपादकीय टिप्पणी:** 'बॉर्डर 2' केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उन गुमनाम नायकों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1971 में तिरंगे की शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारी शांति की कीमत हमारे सैनिकों का रक्त है।

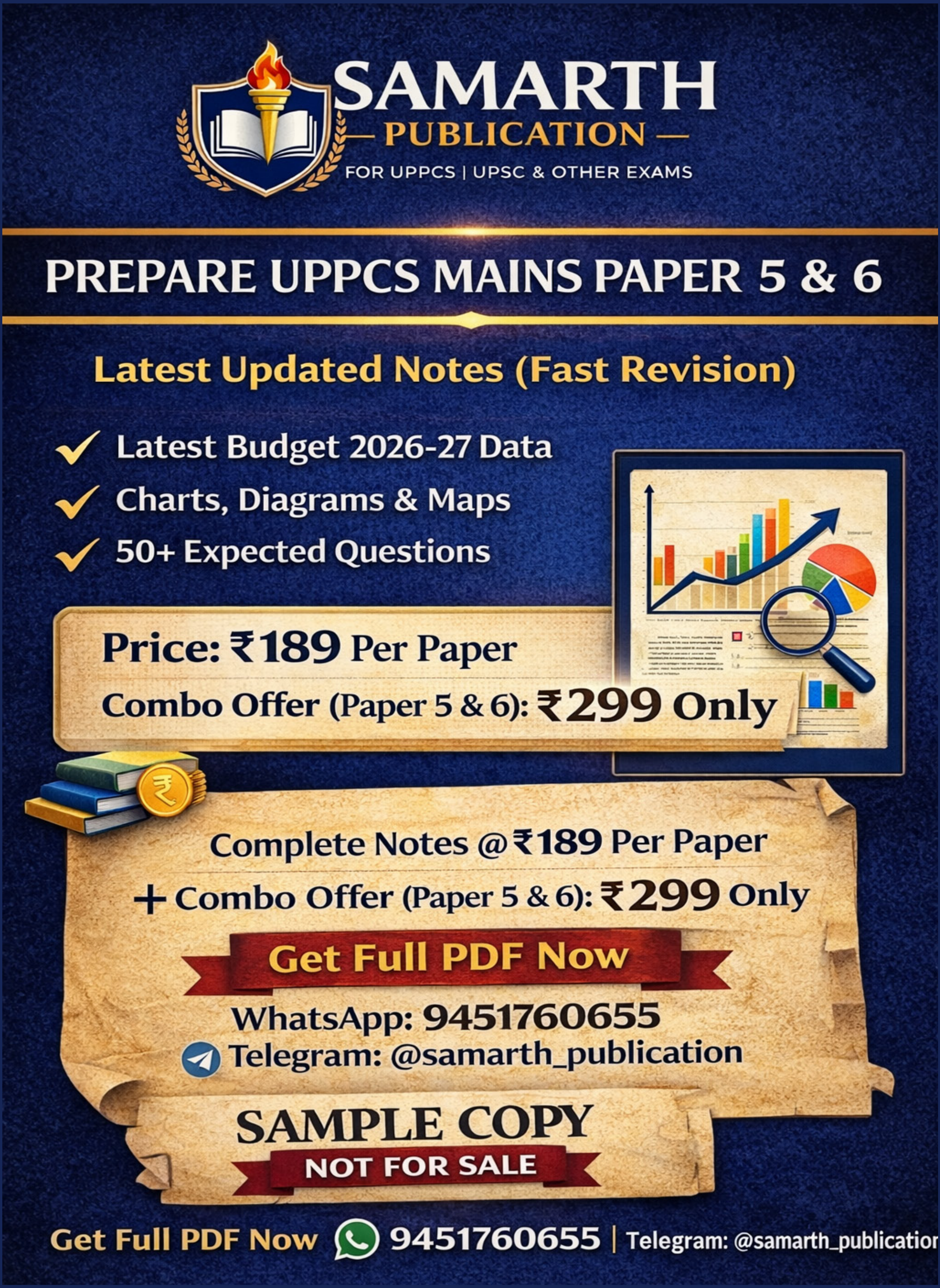
SAMARTH
— PUBLICATION —
FOR UPPCS | UPSC & OTHER EXAMS
PREPARE UPPCS MAINS PAPER 5 & 6
Latest Updated Notes (Fast Revision)
Latest Budget 2026-27 Data
Charts, Diagrams & Maps
50+ Expected Questions
Price: ₹189 Per Paper
Combo Offer (Paper 5 & 6): ₹299 Only
Complete Notes @₹189 Per Paper
+ Combo Offer (Paper 5 & 6): ₹299 Only
Get Full PDF Now
WhatsApp: 9451760655
Telegram: @samarth_publication
SAMPLE COPY
NOT FOR SALE
Get Full PDF Now 9451760655 | Telegram: @samarth_publicatio

News Drift

Changing News Trend

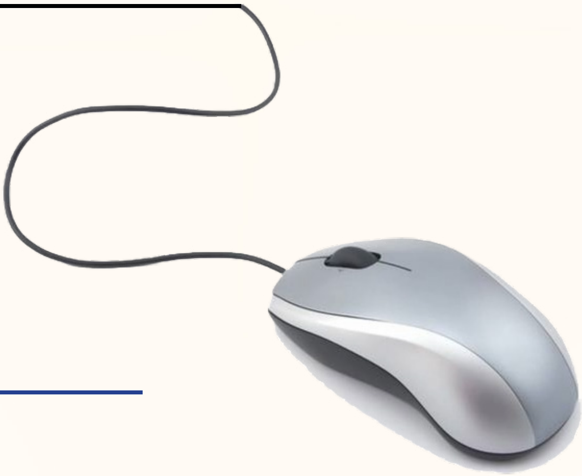

Online

News Portal

Stay

UPTO DATE

www.newsdrift.in

Email- newsdrift19@gmail.com

Instagram- newsdrift.official